सुरक्षा, शांति और समृद्धि

सजग भारत

16 जुलाई से 15 अगस्त, 2023 वर्ष-1 अंक-8/9

निःशुल्क प्रति

आने वाली पीढ़ी को देना है आपदा प्रतिरोधी

भारत का उपहार

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

अनुक्रमणिका

पांच वर्षों में बदली राष्ट्रीय अग्निशमन की तस्वीर 13

सीडीआरआई : वैश्विक भलाई के लिए भारत की पहल 14

हर भारतीय का विश्वास 16

कश्मीर और पूर्वोत्तर में विकास का नया दौर 18

संघीय व्यवस्था सहित भ्रष्टाचार मुक्त शासन... 20

प्रकृति के प्रति कटिबद्ध 23

एक साल में 10 लाख किलोग्राम मादक पदार्थों... 25

केंद्रीय गृह मंत्री ने किया इंडो-पाक सीमा का दौरा 26

भारतीय भाषाओं के प्रसार के लिए अनुकूल समय 28

आपदा प्रबंधन में वैश्विक मानक स्थापित करने में सक्षम... 30

विशेष रिपोर्ट

05 आने वाली पीढ़ी को देना है आपदा प्रतिरोधी भारत...

09 जीरो कैजुअलिटी की ओर बढ़ती भारत की आपदा नीति

11 दुनिया मान रही एनडीआरएफ का लोहा

संपादक की कलम से

बालाजी श्रीवास्तव
महानिदेशक, बीपीआरएंडडी

आपदाएं अचानक आती हैं और सामान्यत: प्राकृतिक ही होती हैं। आपदाओं को रोकने के लिए प्रकृति से लड़ा नहीं जा सकता, परंतु सूझ-बूझ, सतर्कता, तत्परता और तैयारी से आपदाओं का असर कम अवश्य ही किया जा सकता है। राहत और बचाव कार्यों के उच्च स्तर से जानमाल की क्षति को कम किया जा सकता है। हाल के वर्षों में सरकार की ओर से इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। बचाव उपकरणों के आधुनिकीकरण के साथ-साथ आपदा प्रबंधन को नवीनतम प्रौद्योगिकी से लैस किया गया है। जिसके कारण आज हमारे आपदा बचाव दल देश ही नहीं, विदेशों में भी अपनी सशक्त उपस्थिति दिखाकर भारत का नाम रौशन कर रहे हैं।

इस वर्ष की शुरूआत में तुर्की और सीरिया में भारतीय बचाव दल की चहुंओर सराहना हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी ने एनडीआरएफ सहित बचाव दल में शामिल तमाम कर्मियों की भूरि-भूरि प्रशंसा की। हाल ही में, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भयंकर प्राकृतिक आपदा से वहां मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गए, जिससे जान-माल को भारी नुकसान पहुंचा। भारत के तटीय क्षेत्रों में चक्रवात का आना एक नैसर्गिक प्रक्रिया सी हो गई है। इस तरह की सभी आपदाओं में एनडीआरएफ और राज्यों की एसडीआरएफ ने बेहतर समन्वय दिखाया है।

अपनी मुस्तैदी, सतर्कता और बेहतरीन रणनीति के साथ काम करके एनडीआरएफ आपदा प्रबंधन में एक भरोसे का नाम बन चुका है। 2015 में हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में टनल दुर्घटना, केदारनाथ सहित उत्तराखंड के कई इलाकों में बादल फटने की घटना हो। बिहार-पश्चिम बंगाल-ओडिशा-असम जैसे राज्यों में आने वाली भयावह बाढ़ हो, हर बार आम जनता सरकारी सहायता के साथ एनडीआरएफ की ओर देखती है। वर्तमान में, एनडीआरएफ में 16 बटालियन शामिल हैं। प्रत्येक बटालियन में इंजीनियरों, तकनीशियनों, इलेक्ट्रीशियन, डॉग स्क्वॉड और चिकित्सा/पैरामेडिक्स सहित 45 कर्मियों की 18 स्व-निहित विशेषज्ञ खोज और बचाव टीमें हैं। सभी 16 बटालियनों को प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं का सामना करने के लिए सुसज्जित और प्रशिक्षित किया गया है। बटालियनों को विशेष रूप से मुश्किलों के बाद ज्वालामुखी, बर्फ, रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु (सीबीआरएन) आदि से उत्पन्न आपात स्थितियों के लिए भी प्रशिक्षित और सुसज्जित किया जाता है।

अब तक आप लोगों ने 'सजग भारत' के विभिन्न विषयों के अंकों को देखा है। हमारा यह प्रयास कैसा है, इस पर अपनी प्रतिक्रिया हमें dg@bprd.nic.in पर दें। आपकी बातें, हमारा हौसला बढ़ाती है।

जय हिंद!

> **प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी का भी मानना है कि आपदा से निपटने के लिए सबका सहयोग जरूरी है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एकीकृत प्रतिक्रिया है। साथ ही, सुधार एक ऐसी प्रणाली है जिससे संभावित प्राकृतिक आपदाओं के खतरे को कम किया जा सकता है।**

भारत को उन बहादुर सेवानिवृत्त सैनिकों पर गर्व है, जिन्होंने सेवा में रहते हुए हमारे देश की रक्षा की है। उनके लिए अधिक सुविधाओं के साथ लागू की गई कल्याणकारी योजनाओं से उनके जीवन स्तर में काफी हद तक सुधार होगा।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

भारतीय न्याय संहिता बिल, भारतीय साक्ष्य बिल और भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल में किए गए बदलाव से देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में सकारात्मक परिवर्तन होगा और पीड़ितों को अधिक से अधिक 3 साल के अंदर पूर्ण न्याय मिल सकेगा।

श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर शांति की राह पर चल पड़ा है। पिछले 9 वर्षों में आतंकी घटनाओं में करीब 70% की कमी और अनुच्छेद-370 हटने के बाद पत्थरबाजी की घटनाओं में 90% की कमी आई है।

श्री नित्यानंद राय
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री

Cometh the hour, cometh the man! Kudos to #MenInBlue for pulling off a historic win in the #AsianChampionsTrophy in Hockey. A cracker of a final to clinch the title for a record 4th time. Your performance has earned the adulation of every Indian. Jai Hind

Shri Nisith Pramanik
Union Minister of State for Home Affairs

हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भारी वर्षा और भूस्खलन से हुई जनहानि अत्यंत दुःखद है। एनडीआरएफ की टीमें स्थानीय प्रशासन के साथ राहत व बचाव कार्यों में लगी हैं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं।

श्री अजय मिश्रा
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री

Get quick assistance in times of distress through 112 Emergency Response Support System. Emergency Response Vehicle (ERV) reaches the spot of the emergency within no time and takes quick action to save lives and provide the all assistance to ensure safety.

Union Home Ministry

आने वाली पीढ़ी को देना है आपदा प्रतिरोधी

भारत का उपहार

हम प्राकृतिक आपदाओं को रोक नहीं सकते, लेकिन बेहतर रणनीति और व्यवस्था बनाकर निश्चित रूप से उनके प्रभावों को कम कर सकते हैं

ब्यूरो

आपदा कई प्रकार की होती है। प्राकृतिक और दैवीय आपदा को रोकना संभव नहीं है। हाल के वर्षों में देश ने एक नहीं, कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है। जानमाल की क्षति हुई है, लेकिन त्वरित राहत एवं बचाव कार्य से व्यापक क्षति को रोका गया है। समय के साथ केंद्र सरकार की पहल पर आपदा प्रबंधन को पहले से अधिक बेहतर बनाया गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के साथ ही राज्यों के आपदा प्रबंधन को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है।

गौर करने योग्य यह है कि श्री नरेन्द्र मोदी ने जैसे ही गुजरात में सत्ता संभाली, आपदाओं में मानवीय क्षति कम करने के लिए गुजरात में सबसे पहले आपदा प्रबंधन अधिनियम लाया गया। साल 2001 में यह शुरूआत की गई। अपने कई कार्यक्रमों के दौरान प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र

> **भारत आज दुनिया भर में आने वाली आपदाओं को लेकर तेजी से रेस्पांस करने की कोशिश करता है। भारत के नेतृत्व में बने आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के गठबंधन से दुनिया के 100 से अधिक देश आज जुड़ चुके हैं। परंपरा और तकनीकी दक्षता हमारी ताकत हैं। इसी ताकत से हम भारत ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए आपदा प्रबंधन से जुड़े बेहतरीन मॉडल तैयार कर सकते हैं।**
>
> **-श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री**

आपदा प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी की 10 सूत्रीय कार्यसूची

- सभी विकास क्षेत्रों को आपदा जोखिम प्रबंधन के सिद्धांतों को अपनाना चाहिए।
- जोखिम कवरेज में गरीब परिवारों, एसएमई, बहुराष्ट्रीय निगमों, राज्यों तक सभी शामिल होने चाहिए।
- महिलाओं का नेतृत्व और अधिक भागीदारी आपदा जोखिम प्रबंधन के केंद्र में होनी चाहिए।
- प्रकृति और आपदा जोखिमों की वैश्विक समझ को बेहतर बनाने के लिए विश्व स्तर पर पहचान कर जोखिम से बचें।
- आपदा जोखिम प्रबंधन प्रयासों की दक्षता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएं।
- आपदा संबंधी मुद्दों पर काम करने के लिए विश्वविद्यालयों का एक नेटवर्क विकसित करें।
- आपदा जोखिम में कमी के लिए सोशल मीडिया और मोबाइल प्रौद्योगिकियों द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का उपयोग करें।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण को बढ़ाने के लिए स्थानीय क्षमता और पहल का निर्माण।
- आपदाओं से सीखने के हर अवसर का उपयोग करें और इसे प्राप्त करने के लिए, हर आपदा के बाद सबक पर अध्ययन होना चाहिए।
- आपदाओं के प्रति अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया में अधिक एकजुटता लाना।

मोदी ने इस बात का उल्लेख किया है। गुजरात पहला राज्य था, जो 2001 में राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम लेकर आया। तत्कालीन केंद्र सरकार ने इसी एक्ट के आधार पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया था। उसके बाद, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अस्तित्व में आया। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच (एनपीडीआरआर) के तीसरे सत्र को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने पिछले वर्षों में पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आए चक्रवातों के कारण हुई सैकड़ों मौतों को याद किया, यह कहते हुए कि रणनीतियों में बदलाव के साथ, भारत अब चक्रवातों से निपटने और उनके कारण होने वाले जान-माल के नुकसान को कम करने में सक्षम है। कहा, हम प्राकृतिक आपदाओं को रोक नहीं सकते, लेकिन बेहतर रणनीति और व्यवस्था बनाकर हम निश्चित रूप से उनके प्रभावों को कम कर सकते हैं।

बीते दशक में प्रधानमंत्री की बातें सच साबित हो रही हैं और आपदा आने की पूर्व सूचना मिलते ही जिस प्रकार से श्री अमित शाह जी की अगुवाई में केंद्रीय गृह मंत्रालय युद्धस्तर पर काम करना शुरू कर देता है, उससे अब मानवीय क्षति शून्य हो रही है। हाल ही में गुजरात के तटीय क्षेत्रों में आए चक्रवात में एक भी व्यक्ति की क्षति नहीं हुई है। यह पूरे देश के लिए गर्व की बात है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी केवल देश के अंदर ही आपदा प्रबंधन को लेकर सचेष्ट हैं। भारत पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानता है। इसी सोच के तहत जब भी किसी देश में आपदा आती है, सहायता की जरूरत होती है, तो भारत मैत्री के तहत कई अभियान चलाता है। कुछ महीने पहले ऑपरेशन दोस्त की सफलता को पूरी दुनिया ने देखा है।

बीते दिनों जब तुर्की में जबरदस्त भूकंप आया, उस त्रासदी को पूरी दुनिया ने देखा। तुर्की में सबसे पहले सहायता लेकर भारत पहुंचा और ऑपरेशन दोस्त ने वहां के लोगों को बचाया गया। पुर्नवास के काम किए गए। इसके लिए उस समय पूरी दुनिया ने भारत सरकार की सराहना की थी। देश के अंदर कई राज्यों में आई आपदा के दौरान बेहतर संघवाद के तहत राहत व बचाव कार्य देखने को मिल रहा है। हाल के वर्षों में कई चक्रवात भारत की तटीय सीमा से टकराया जरूर, लेकिन सटीक आपदा प्रबंधन के कारण अपेक्षित विनाश नहीं कर पाया।

दरअसल, जैसे ही साल 2014 में श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री का दायित्व संभाला, उसके बाद कई समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर देखा और समझा। उसमें से ही एक आपदा प्रबंधन भी रहा। कई अवसरों पर प्रधानमंत्री ने आजादी के बाद के वर्षों में आपदा प्रबंधन की खराब स्थिति के बारे में बात की है। उनका कहना है कि पांच दशक बीत जाने के बाद भी आपदा प्रबंधन को लेकर कोई कानून नहीं था। गुजरात पहला ऐसा राज्य था, जो 2001 में राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम लेकर आया। तत्कालीन केंद्र सरकार ने इस अधिनियम के आधार पर आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया। इसके बाद, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अस्तित्व में आया। 10 मार्च,2023 को प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण

वर्ष 2001 में बतौर मुख्यमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने आपदा प्रबंधन की महत्ता को समझा और गुजरात पहला राज्य बना, जहां आपदा प्रबंधन अधिनियम लाया गया। बीते नौ वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी की दूरदृष्टि ने नई आपदा नीति को लेकर खूब काम किया।

के लिए राष्ट्रीय मंच (एनपीडीआरआर) के तीसरे सत्र का उद्घाटन किया था। इस मंच के तीसरे सत्र की मुख्य थीम बदलती जलवायु में स्थानीय स्तर पर मजबूती सुनिश्चित करना रखा गया था। एनपीडीआरआर आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में संवाद, अनुभवों, विचारों, कार्रवाई उन्मुख अनुसंधान को साझा करने और अवसरों का पता लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित एक बहु-हितधारक मंच है।

प्रधानमंत्री ने प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वास्तविक समय में पंजीकरण और निगरानी प्रणाली की बात कही। उन्होंने कहा, घरों के टिकाऊपन, जल निकासी, बिजली और पानी के बुनियादी ढांचे के लचीलेपन जैसे पहलुओं के संबंध में जानकारी से सक्रिय कदम उठाने में मदद करेगी। अपने संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि भारत दुनिया भर में होने वाली आपदाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है और मजबूत इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए पहल करता है। उन्होंने बताया कि दुनिया के 100 से अधिक देश भारत के नेतृत्व में गठित हुए 'कोलिएशन फॉर डिजास्टर रजीलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर' में शामिल हो गए हैं। उन्होंने भरोसा व्यक्त किया कि आज की चर्चाओं से बहुत सारे सुझाव और समाधान निकलेंगे तथा इससे भविष्य के लिए कई कार्रवाई योग्य बिंदु सामने आएंगे। उन्होंने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, परंपरा और प्रौद्योगिकी हमारी ताकत हैं, और इस ताकत के साथ हम न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए आपदा प्रतिरोध से संबंधित सर्वश्रेष्ठ मॉडल तैयार कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना शुरू की थी। इसमें शामिल है- सतर्कता, सावधानी, राहत, सुरक्षा और

विशेष बातें

- गुजरात पहला ऐसा राज्य था, जो 2001 में राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम लेकर आया। तत्कालीन केंद्र सरकार ने इस अधिनियम के आधार पर आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू किया। इसके बाद, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अस्तित्व में आया।
- दुनिया के 100 से अधिक देश भारत के नेतृत्व में गठित हुए 'कोलिएशन फॉर डिजास्टर रजीलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर' में शामिल हो गए हैं।
- पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के इनीशिएटिव के कारण अर्ली वॉर्निंग, सक्रिय निवारण, मिटिगेशन और पूर्व तैयारी-आधारित डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के साथ अप्रोच में बदलाव आया है और इसके अच्छे परिणाम मिले हैं।
- फरवरी, 2021 में नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड का गठन किया गया और इसके अंतर्गत 13 हजार 700 करोड़ रूपए केन्द्र और 32 हजार करोड़ रूपए राज्यों द्वारा रखे गए हैं।
- सरकार ने 350 उच्च-जोखिम आपदा संभावित ज़िलों में लगभग एक लाख युवा वॉलंटियर को तैयार करने का लक्ष्य रखा है, इससे आपदाओं के समय हमें बहुत अच्छे नतीजे मिल रहे हैं।
- 2005-06 से 2013-14 तक और 2014-15 से 2022-23 तक के 9 सालों की तुलना करने पर, एसडीआरएफ को जारी होने वाले ₹35,858 करोड़ अब लगभग तीन गुणा बढ़कर ₹1,04,704 करोड़ हो गए।
- एनडीआरएफ से जारी होने वाली राशि ₹25,000 करोड़ से बढ़कर, लगभग तीन गुणा वृद्धि के साथ ₹77,000 करोड़ हो गई है।
- प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के माध्यम से आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में योगदान देने वाले व्यक्ति और संस्था को पुरस्कृत करने की परंपरा शुरू की है, इससे निश्चित रूप से इस क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं का उत्साहवर्धन हुआ है।

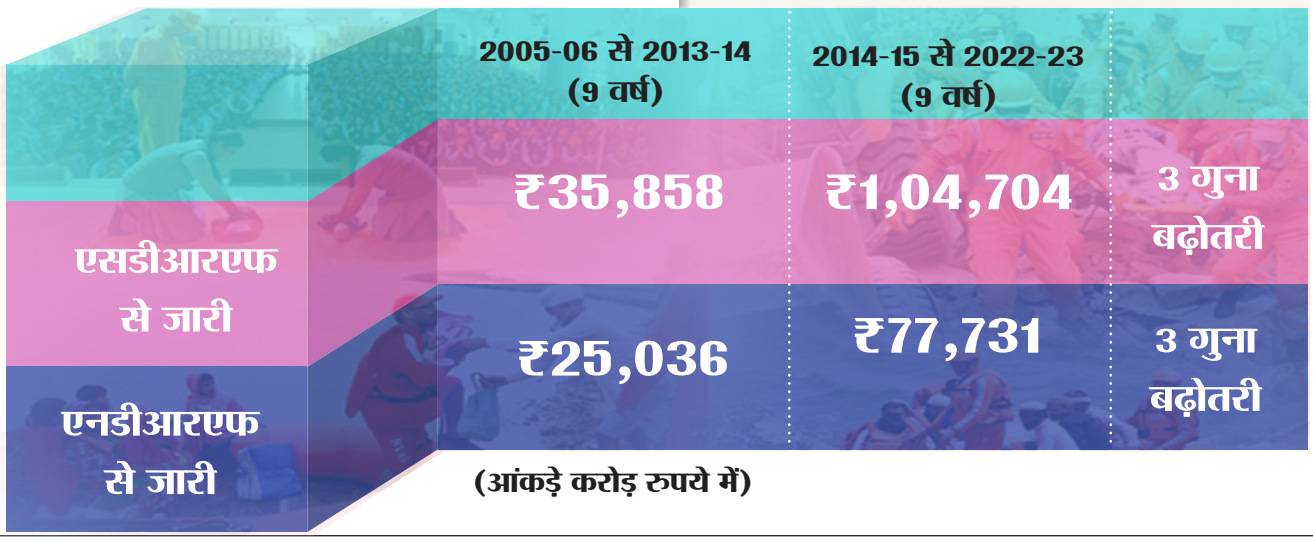

पुनर्वास का एकीकृत दृष्टिकोण। ये राहत-केंद्रित है, चेतावनियों के बारे में पहले बताता है, सक्रिय रोकथाम करता है, पूर्व तैयारियों के आधार पर जोखिम कम करते हुए शांति फैलाता है। 350 बहु-खतरा-प्रवण जिलों में डिजास्टर फ्रेंड स्कीम को स्थापित और कार्यान्वित किया गया। इसका मकसद था, एक लाख से अधिक युवा स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करना। आईडीआरएन (भारत आपदा संसाधन नेटवर्क) एक राष्ट्रव्यापी इलेक्ट्रॉनिक सूची है, जिसमें 01 जनवरी 2022 और 19 जून 2023 के बीच 2,99,121 नए रिकॉर्ड अपडेट किए गए हैं। 2 जनवरी, 2020 में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) अकादमी की आधारशिला नागपुर में रखी। इसके माध्यम से लाख से अधिक युवा स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के साथ 350 बहु-खतरा-प्रवण जिलों में एक आपदा मित्र योजना स्थापित और कार्यान्वित की गई, जिनका सरकार द्वारा बीमा किया जाएगा।

आपदा मित्र योजना को कुल 369 .41 करोड़ के व्यय के साथ मंजूरी दी गई। मोबाइल फोन के माध्यम से आपात स्थिति और आपदाओं से संबंधित भौगोलिक दृष्टि से तत्काल अलर्ट प्रदान करने के लिए ₹354 करोड़ के व्यय के साथ मार्च 2021 में एक कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल (सीएपी) शुरू हुआ। आपदा क्षति पर क्षेत्र-विशिष्ट डेटा इकट्ठा करने और आपदा जोखिम न्यूनीकरण (एसएफडीआरआर) के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क के चार (04) लक्ष्यों के तहत विभिन्न संकेतकों पर निगरानी करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन सूचना प्रणाली (एनडीएमआईएस) पोर्टल भी लॉन्च किया गया। आपदा आपातकालीन स्थितियों के लिए, ₹41 करोड़ के व्यय के साथ 'डायल 112' आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) को मंजूरी दी गई। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए भारतीय विश्वविद्यालय और संस्थान नेटवर्क (आईयूआईएन-डीआरआर-एनआईडीएम) भी स्थापित किया गया था, जिसमें अब तक 251 विश्वविद्यालय शामिल हैं। ■

रासायनिक और परमाणु आपदाओं के लिए भी तैयार है एनडीएमए

वर्तमान के साथ भविष्य में संभावित रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु (सीबीआरएन) खतरों के लिए तैयारी बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। ये परियोजनाएं पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों को मोबाइल रेडिएशन डिटेक्शन सिस्टम, विशेष गियर और रेडियोलॉजिकल आपात स्थितियों के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण से लैस करती हैं।

इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्रों को संभावित रेडियोलॉजिकल खतरों से सुरक्षित करना है। एनडीएमए ने एक परियोजना 'मोबाइल विकिरण जांच प्रणाली' कार्यान्वित किया है, जिसके तहत पुलिस कर्मियों को सार्वजनिक क्षेत्रों में विकिरणकीय आपात स्थियति के प्रबंधन में समर्थ बनाया और प्रशिक्षित किया गया है। इस परियोजना के तहत चयनित शहरों में पुलिस कर्मियों को पीपीई, विकिरण डिटेक्टशर जिसमें गो-नोगो विकिरण मीटर युक्त वाहन शामिल है, प्रदान किया गया है। परियोजना में शामिल सभी शहरों के पुलिस कर्मियों की एक अनुपातिक संख्या में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत तथ्यों में प्रशिक्षण दिलाया गया है।

एनडीएमए द्वारा समय-समय पर प्रमुख हवाई अड्डों और बंदरगाहों के कर्मचारियों को भी सीबीआरएन प्रबंधन प्रशिक्षण दिया गया है। इस प्रशिक्षण को कई बंदरगाहों तक विस्तार देने की योजना है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों वाले क्षेत्रों में जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं (डीडीएमपी) को एकरूपता और विस्तार के लिए अद्यतन किया जा रहा है। साल 2019 में, परमाणु और रेडियोलॉजिकल आपात स्थितियों के चिकित्सा प्रबंधन पर एक विशेष मैनुअल प्रकाशित किया गया था, जो आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका है। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ की चिकित्सा शाखा ने 7 से 10 फरवरी, 2023 तक सेना अस्पताल (अनुसंधान और रेफरल) में सीबीआरएन चिकित्सा प्रबंधन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया था। कार्यशाला में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, चिकित्सा सेवा और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के 60 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

कार्यशाला में प्रशिक्षण मॉड्यूल की एक श्रृंखला शामिल थी, जिसमें सीबीआरएन खतरों और प्रबंधन पर व्याख्यान, सीबीआरएन अभ्यासों का प्रदर्शन और सीबीआरएन उपकरणों के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल था। इसमें सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज और परमाणु चिकित्सा संस्थान जैसे संस्थानों के विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण दिया था। प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्याख्यान के साथ ही फील्ड ट्रेनिंग तथा सीबीआरएन पदार्थों की पहचान करने और उनसे बचाव के उपकरणों का प्रदर्शन शामिल है। प्रशिक्षण कार्यक्रम हवाई अड्डों पर आपात स्थितियों से निपटने के लिए तैनात सुरक्षाकर्मियों -एईएच को सीबीआरएन से उत्पन्न आपात स्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम बनाने के साथ ही उन्हें तत्काल प्राथमिक उपचार और मनोवैज्ञानिक मदद देने में भी समर्थ बनाना था।

जीरो कैजुअलिटी की ओर बढ़ती भारत की आपदा नीति

ब्यूरो

नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। आम दिनों के साथ ही आपदा के समय में सरकार की पहली प्राथमिकता जान माल की क्षति को रोकना और प्राकृतिक आपदा के समय इसे कम करना होता है। संचार के आधुनिक संसाधनों से पहले की तुलना में कई सूचनाएं पूर्व में ही मिलती है। इसके आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय तुरंत युद्धस्तर की तैयारी करता है। संबंधित राज्यों के प्रशासनिक और संबंधित विभाग को भी एक्टिव मोड में काम करने के लिए कहा जाता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बेहतर समन्वय से हाल के वर्षों में बेहतर आपदा प्रबंधन देखने को मिला है। कुछ समय पहले जब बिपरजॉय गुजरात के समुद्री तटों से टकराया तब कई मील की तेज रफ्तार से आंधियां चल रही थीं। उस समय सरकार की तत्परता ने एक भी नागरिक की मौत नहीं होने दी। केंद्र सरकार आपदा के समय भी शून्य क्षति का लक्ष्य लेकर बेहतर समन्वय का उदाहरण पूरी दुनिया के सामने पेश कर रही है।

10 मार्च, 2023 नई दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय मंच (एनपीडीआरआर) के तीसरे सत्र का आयोजन किया गया था। इस मंच के तीसरे सत्र की मुख्य थीम 'बदलती जलवायु में स्थानीय स्तर पर मजबूती सुनिश्चित करना' रखा गया था। इस दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री,

> **आपदाओं का स्वरूप बदला है, उनकी फ्रीक्वेंसी और तीव्रता भी बढ़ी है, इसीलिए हमें अपनी तैयारियों को अधिक पैना और व्यापक करना होगा। अब कई नए स्थानों पर नई आपदाएं आ रही हैं, इसके लिए भी हमें अपने आप को तैयार करना होगा। पहले आपदा के प्रति हमारा दृष्टिकोण राहत-केंद्रित और रिएक्शनरी था, प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में 9 सालों में अर्ली वॉर्निंग सिस्टम, प्रिवेंशन, मिटिगेशन और पूर्व तैयारी-आधारित आपदा प्रबंधन को हमने सामूहिक मेहनत और लगन से जमीन पर उतारा है।**
>
> **- श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**

श्री अमित शाह ने भी अपना वक्तव्य दिया था। उनके अनुसार, 1999 से लेकर आज तक के परिदृश्य में बहुत बड़ा बदलाव आया है क्योंकि साझा प्रयासों के कारण हमने न सिर्फ आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करने

में सफलता हासिल की है, बल्कि अच्छी व्यवस्था के साथ पड़ोसियों को मदद करने और पूरे क्षेत्र में अर्ली वॉर्निंग सिस्टम स्थापित करने की दिशा में भी अनुकरणीय काम किया है। श्री शाह ने कहा कि भारत आपदा से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों में से एक है और 36 राज्यों और संघशासित प्रदेशों में से 27 राज्य और संघशासित प्रदेश आपदा-संभावित हैं। भारत की लगभग 50 प्रतिशत से अधिक आबादी भूकंप, बाढ़, समुद्रीय और तटीय चक्रवात, सूखे और सूनामी से प्रभावित है। प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण को बदलने का काम किया है।

राज्यों से संवाद

आपदा प्रबंधन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय लगातार राज्यों से संवाद करता रहता है। आपदा राहत कर्मियों से संवाद होता रहा है। इसी कड़ी में 5 अगस्त, 2023 को केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने भुवनेश्वर में एक बैठक में ओडिशा में आपदा प्रबंधन और वामपंथी उग्रवाद की समीक्षा की। बैठक में ओडिशा के मुख्यमंत्री, श्री नवीन पटनायक, केंद्रीय गृह सचिव और गृह मंत्रालय व राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। श्री अमित शाह ने आपदा प्रबंधन के लिए राज्य द्वारा की गयी तैयारियों की सराहना की, जिसमें 1999 में आए भीषण चक्रवाती तूफान के बाद से काफी प्रगति हुई है। उन्होंने सलाह दी कि राज्य में आपदा मित्रों और आपदा वॉरियर्स को बहु-आपदा ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, विशेष रूप से रासायनिक व परमाणु आपदाओं और ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए जो कि बिना किसी चेतावनी के घटित होती हैं। यह सुझाव भी दिया कि होम गार्ड स्वयंसेवकों को मजबूत किया जाना चाहिए और उन्हें आपदा प्रतिक्रिया संबंधी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, राज्य में स्थापित बहुउद्देश्यीय चक्रवात आश्रयों के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए बजट मद में से नियमित रुप से धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने राज्य प्रशासन को मानक संचालन प्रक्रियाएं अपनाने और बिजली, लू व जंगल की आग से लोगों की जान बचाने के लिए उचित तैयारी और शमन के प्रयास करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आपदाओं के दौरान जानवरों की सुरक्षा पर भी ध्यान देने पर जोर दिया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने बालासोर ट्रेन दुर्घटना के दौरान उत्कृष्ट सहयोग के लिए राज्य सरकार को धन्यवाद दिया और ग्राम स्तर के स्वयंसेवकों व पूरे राज्य के प्रशासन तंत्र के प्रयासों की सराहना की।

बेहतर समन्वय

समय-समय पर कई राज्य आपदा की चपेट में आते हैं। हर राज्य केंद्र सरकार के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करे और उसे त्वरित सहायता उपलब्ध हो, इस उद्देश्य को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली में राज्यों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों की एक उच्चस्तीय बैठक बुलाई। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विजन@2047 के तहत भारत को आपदा प्रतिरोधी बनाने के लिए देश में आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली को और मजबूत करना था। बैठक के दौरान आपदा की पूर्व तैयारी, शमन, प्रतिक्रिया, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा, पूर्व चेतावनी और प्रसार प्रणाली, शमन निधि का उपयोग, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बलों (एसडीआरएफ) की स्थापना और मजबूती, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (एसडीएमए) और

केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने 13 जून, 2023 को देश में आपदा प्रबंधन के लिए ₹8000 करोड़ से अधिक की तीन प्रमुख योजनाओं की घोषणा की।

- **राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए ₹5,000 करोड़ की परियोजना।**
- **सबसे अधिक आबादी वाले सात महानगरों (मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे) में शहरी बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए ₹2,500 करोड़ की परियोजना।**
- **17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भूस्खलन शमन के लिए ₹825 करोड़ की राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण परियोजना।**

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए), आपदा तैयारियों, प्रतिक्रिया और शमन आदि में समुदाय द्वारा वॉलंटियर स्वयंसेवा को प्रोत्साहित करने से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। राज्य सरकारों और केन्द्रशासित प्रदेशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने बैठक के दौरान उठे मुद्दों पर हुई चर्चा के बारे में बहुमूल्य जानकारी साझा की। उन्होंने अपने-अपने राज्यों द्वारा अपनाई जा रही सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया और आपदा प्रबंधन में सामने आने वाली चुनौतियों पर अपने विचार भी रखे। बैठक के दौरान इस बात का संज्ञान लिया गया कि केंद्र और राज्यों ने मिलकर पिछले नौ वर्षों में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। बैठक में इस बात पर फिर जोर दिया गया कि निर्बाध निष्पादन के साथ टीम प्रयास से किसी भी आपदा के दौरान जान और माल के साथ-साथ आजीविका और संपत्ति का भी न्यूनतम नुकसान होगा।

नौ वर्षों की उपलब्धि

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि बैठक में हुई चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर नीतियों को बनाने और उनमें बदलाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले नौ वर्षों में केन्द्र और राज्यों ने काफी उपलब्धियां प्राप्त की हैं, लेकिन हम इससे संतुष्ट होकर नहीं बैठ सकते हैं। उन्होंने कहा कि आपदाओं का स्वरूप बदला है और उनकी फ्रीक्वेंसी और तीव्रता भी बढ़ी है, इसीलिए हमें अपनी तैयारियों को इसके साथ अधिक पैना और व्यापक करना होगा। अब कई नए स्थानों पर नई आपदाएं आ रही हैं, इसके लिए भी हमें अपने आप को तैयार करना होगा। चाणक्य के अर्थशास्त्र से लेकर पौराणिक समय के राज्य प्रशासन के जितने भी दस्तावेज उपलब्ध हैं उन सभी में आपदा प्रबंधन की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि कोविड के संकट काल के समय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर देश सदी की सबसे भीषण महामारी का सामना करके उससे बाहर निकला। उस कठिन समय में सभी मोर्चे पर केंद्र, राज्य और जनता तीनों ने मिलकर आपदा के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी जा सकती है उसका एक उत्कृष्ट उदाहरण दुनिया के सामने रखा। वर्ष 2021 में केन्द्र सरकार के तहत 16,700 करोड़ रूपए से नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड का गठन किया गया था और एसडीएमएफ के तहत 32,000 करोड़ रूपए शमन गतिविधियों के लिए रखे गए हैं। ■

ऑपरेशन दोस्त

दुनिया मान रही एनडीआरएफ का लोहा

ब्यूरो

फरवरी, 2023 में तुर्की में जबरदस्त भूकंप आया। भारत सरकार की ओर से ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तुरंत राहत एवं बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ को तुर्की भेजा। इस कार्य में भारतीय वायुसेना और अन्य विभागों ने बेहतर सामंजस्य दिखाया। सबका मसकद त्रासदी से जूझ रहे लोगों को तुरंत राहत पहुंचाना था। कई दिनों की ऑपरेशन के बाद एनडीआरएफ ने कई लोगों की जान बचाई।

तुर्की में भीषण भूकंप की सूचना मिलते ही, भोजन, दवा आदि राहत सामग्री लेकर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) का दल तुर्कीवासियों के मदद के लिए निकल पड़ा। हजारों लोगों को नया जीवनदान देने के बाद जब एनडीआरएफ टीम भारत वापसी के लिए विदा हो रही थी, तो तुर्कीवासियों ने टीम के सदस्यों को तालियां बजाकर विदाई दीं।

भूकंप से बेहाल तुर्की को जब मदद की जरूरत पड़ी, तो भारत ने सबसे पहले मोर्चा संभाला। सरकार ने एनडीआरएफ को राहत और बचाव कार्य के लिए भेजा। भारत सरकार ने 24 घंटे के अंदर सेना के फील्ड अस्पताल को भी तुर्की में स्थापित किया, जहां 10 से ज्यादा डॉक्टरों और 99 मेडिकल स्टॉफ की तैनाती की गई। इन लोगों की सहायता करने में तुर्की सरकार को परेशानी से बचाने के लिए भारत ने हवाई जहाज से ट्रक, टेंट, एक्ट्रीम कोल्ड वेदर सूट, स्लीपिंग बैग, मेडिकल उपकरण, बेड और दवाइयां भी भेजी। भारतीय टीम ने घायल नागरिकों के सैकड़ों छोटे-बड़े ऑपरेशन किए।

6 फरवरी को तुर्की और सीरिया में आए 7.8 तीव्रता के भूकंप के कारण 45,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और दस लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए। इस संकट के समय तुर्किए और सीरिया में सबसे पहले मदद पहुंचाने वालों में भारत शामिल था। भारत ने दोनों देशों में पीड़ितों की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया। भूकंप के बाद मदद करने पहुंची एनडीआरएफ और सेना के फील्ड हॉस्पिटल की टीम ने सैकड़ों तुर्की लोगों की न केवल जान बचाई बल्कि हजारों की संख्या में घायल लोगों का इलाज भी किया। बड़ी बात यह रही कि इस मदद के लिए भारतीय टीम ने वहां की सरकार पर निर्भर न होते हुए सारा साजोसामान खुद लेकर गई थी। रही बात मेडिकल सप्लाई की तो उसे भारत से लगभग रोजाना विमानों के जरिए तुर्किये पहुंचाया गया।

जब भारत सरकार की ओर से राहत सामग्री और एनडीआरएफ की टीम को लेकर पहली खेप गई, तो उस उड़ान में 35 टन मानवीय सहायता, राहत सामग्री, चिकित्सा सहायता, आपातकालीन और महत्वपूर्ण देखभाल दवाएं, चिकित्सा उपकरण और उपभोग्य वस्तुएं थीं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि भारतीय टीमें भूकंप प्रभावित तुर्की में राहत और बचाव कार्यों में मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त के तहत दिन-रात काम कर रही हैं। एनडीआरएफ ने तुर्की में चलाए जा रहे ऑपरेशन दोस्त के दौरान एक 6 साल की बच्ची की जान बचाई। इसको लेकर जैसे ही वीडियो शेयर किया गया, वह वायरल हो गया। इस वीडियो में एनडीआरएफ की टीम के जवानों द्वारा एक बच्ची को मलबे से बचाते हुए देखा गया। है।

इस बच्ची का नाम बेरेन है। इस वीडियो को भारत सरकार के केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया। है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा 'हमें अपने एनडीआरएफ पर गर्व है। तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान भारतीय जवानों ने गजियांटेप शहर में एक छह साल की बच्ची बेरेन की जान बचाई। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में हम एनडीआरएफ को दुनिया का सबसे अग्रणी आपदा प्रतिक्रिया बल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।' 'ऑपरेशन दोस्त' की टीम जब स्वदेश लौटी तो प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि ऑपरेशन दोस्त से जुड़ी पूरी टीम, एनडीआरएफ हो, सेना हो, वायुसेना हो या हमारी दूसरी सेवाओं के साथी हों, सभी ने बेहतरीन काम किया है। यहां तक कि हमारे बेजुबान दोस्तों डॉग स्क्वॉड के सदस्यों ने भी अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन किया है।

हाल के वर्षों में जब भी प्राकृतिक आपदा या कोई बड़ी दुर्घटना होती है, तो लोगों की उम्मीद एनडीआएफ पर आकर टिक जाती है। जैसे ही केंद्र सरकार की सहायता के साथ एनडीआरएफ की टीम उस विशेष क्षेत्र में पहुंच जाती है, लोगों को पूरा भरोसा हो जाता है कि वो अब बच जाएंगे। इस बात को स्वयं प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी भी कह चुके हैं।

एनडीआरएफ के समर्पण और प्रतिबद्धता को उनका आदर्श वाक्य बखूबी दशार्ता है-'आपदा सेवा सदैव सर्वत्र'। जिस तरह से आपदा के समय एनडीआरएफ के कर्मी अपनी सेवा में तत्परता, ईमानदारी, व्यावसायिकता और समर्पण दशार्ते हैं, उससे एनडीआरएफ को सभी के बीच लोकप्रिय बनाया है। अक्टूबर 2014 में जब चक्रवात हुदहुद ने पूर्वी भारतीय तट पर तबाही मचाई, तो प्रभावित लोगों की जान बचाने के लिए एनडीआरएफ कर्मी वहां मौजूद थे। उन्होंने बड़े पेड़ों और अन्य धातु की वस्तुओं को काटने के लिए आरी कटर का उपयोग किया, जिनके हुद-हुद की तेज और क्रूर हवाओं के कारण उखड़ जाने और बिखर जाने की संभावना थी। जब 25 अप्रैल 2015 को, नेपाल में 7.8 की तीव्रता और 15 किमी की गहराई वाला भूकंप आया, तो भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल ने जमीन पर सबसे पहले आपदा प्रबंधन के सुनहरे घंटों के नियम का फायदा उठाकर सुर्खियां बटोरीं। ■

ऑपरेशन दोस्त, मानवता के प्रति भारत के समर्पण और संकट में फंसे देशों की मदद के लिए तत्काल खड़े होने के हमारे कमिटमेंट को भी दर्शाता है। दुनिया में कहीं भी आपदा हो, भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में तैयार मिलता है। नेपाल का भूकंप हो, मालदीव में, श्रीलंका में संकट हो, भारत सबसे पहले मदद के लिए आगे आया था। अब तो भारत की सेनाओं के साथ-साथ एनडीआरएफ पर भी देश के अलावा दूसरे देशों का भरोसा बढ़ता जा रहा है। मुझे खुशी है कि बीते वर्षों में एनडीआरएफ ने देश के लोगों में एक बहुत अच्छी साख बनाई है। देश के लोग कहीं पर भी संकट की संभावना हो, साइक्लोन हो, जैसे ही आपको देखते हैं तो आप पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। आपकी बात मानना शुरू कर देते हैं। संकट की किसी घड़ी में चाहे वो साइक्लोन हो, बाढ़ हो या फिर भूकंप जैसी आपदा, जैसे ही एनडीआरएफ की वर्दी में आप और आपके साथी फील्ड पर पहुंचते हैं, लोगों की उम्मीद लौट आती है, विश्वास लौट आता है।

-श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

पांच वर्षों में बदल रही है राष्ट्रीय अग्निशमन की तस्वीर

ब्यूरो

आग से होने वाली घटनाएं होती है, तो बहुत कुछ तबाह हो जाता है। जान-माल की व्यापक क्षति होती है। इसे रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय देश में लगातार अग्निशमन सेवा का विस्तार कर रहा है। इस कार्य में राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर अग्रणी संस्थान के रूप में मार्गदर्शन कर रहा है। साल 2020 के जनवरी में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय के नये परिसर को राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) अकादमी की आधारशिला रखी। इसे गौरव का क्षण बताते हुए उन्होंने कहा कि पांच हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने में प्रभावी दमकल सेवा एवं आपदा प्रबंधन अहम है। उन्होंने कहा कि दमकल सेवा एवं आपदा प्रबंधन को इससे पहले नजरअंदाज किया जाता था।

यद्यपि अग्निशमन सेवा राज्य का विषय है, फिर भी श्री शाह ने उम्मीद जताई कि एनएफएससी के माध्यम से सभी राज्य केंद्र के साथ अग्नि से जुड़ीं आपदाओं के नियंत्रण में बेहतर तालमेल बैठाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार ने एनएफएससी के आधुनिकीकरण के लिए 200 करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित की है। गृह मंत्री ने कहा है कि यह गर्व की बात है कि 2016 से मोदी सरकार के निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप एनडीआरएफ वैश्विक स्तर पर अग्रणी आपदा प्रबंधन बल के रूप में उभरा है और आपदा जोखिम कमी के लिए सेंडई फ्रेमवर्क के अंतर्गत सभी मानकों को पूरा किया है। श्री शाह ने कहा कि देश ने आपदा मोचन में पिछले दो दशकों में सराहनीय काम किया है और मानव जीवन तथा अर्थव्यवस्था के नुकसान को कम करने में अपनी क्षमताओं में सुधार किया है। श्री शाह ने कहा कि भारत सार्क क्षेत्र में आपदा प्रबंधन कर्मियों के प्रशिक्षण का केंद्र बन गया है। इससे श्रेष्ठ व्यवहारों के आदान-प्रदान में मदद मिलेगी और लोगों पर आपदा के प्रभावों में कमी आएगी। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आपदा से सक्षमता के साथ मुकाबला करने के लिए भारत को तैयार रहने की आवश्यकता है और निकट भविष्य में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपदा अवसंरचना को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। ■

> **सरकार ने 70 वर्षों से उपेक्षित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन तथा अग्नि सेवाओं को प्राथमिकता दी है। एनएफएससी के आधुनिकीकरण के लिए ₹200 करोड़ से अधिक का आवंटन किया। आपदा मोचन व्यवस्था में विशाल क्षमता सृजन के कारण आपदा के समय जान-माल का नुकसान पिछले 10 वर्षों में एक प्रतिशत से कम रह गया है।**
>
> **- श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**

- केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने ₹5,000 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ 'राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए योजना' शुरू की
- कुल परिव्यय में से ₹500 करोड़ की राशि राज्यों को उनके कानूनी और बुनियादी ढांचा-आधारित सुधारों के आधार पर प्रोत्साहित करने के लिए रखी गई है।
- योजना के तहत परियोजनाओं/प्रस्तावों के लिए धन आवंटन के लिए, संबंधित राज्य सरकारों को इन परियोजनाओं/प्रस्तावों की कुल लागत का 25% (उत्तर-पूर्वी और हिमालयी (एनईएच) राज्यों को छोड़कर, जो 10% योगदान देंगे) अपने बजटीय संसाधन में से योगदान करना होगा।
- एनएफएससी के इतिहास में पहली बार कॉलेज ने बीई फायर इंजीनियरिंग के 26वें बैच के लिए दीक्षांत परेड का आयोजन किया।
- नेशनल फायर सर्विस कॉलेज ने 'अग्नि' थीम पर अग्निशमन सेवा सप्ताह 2023 मनाया।
- बीई फायर इंजीनियरिंग (2019-23) के 26वें बैच को 100 प्रतिशत का रिकॉर्ड मिला है। अग्रणी पीएसयू और पेट्रोकेमिकल दिग्गजों सहित देश की कंपनियों ने भर्ती की है।

सीडीआरआई : वैश्विक भलाई के लिए भारत की पहल

ब्यूरो

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने 23 सितंबर, 2019 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन 2019 के दौरान, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (सीडीआरआई) के रूप में एक वैश्विक पहल की शुरूआत की। सीडीआरआई की घोषणा विश्व नेताओं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों और दुनिया भर के राजनयिकों की उपस्थिति में की गई थी। भारत की कोशिश है कि इस मंच पर दुनिया के 100 देश जुटे और एक साथ मिलकर आपदा का मुकाबला करें। एक देश आपातकाल की स्थिति में दूसरे की सहायता करें।

सीडीआरआई का मुख्यालय दिल्ली में है। प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने शिक्षा, मूल्यों, जीवन शैली और विकास दर्शन को शामिल करते हुए एक व्यापक दृष्टिकोण के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आपदाओं के सामने हमारे बुनियादी ढांचे को लचीला बनाने के लिए, भारत आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए एक गठबंधन शुरू कर रहा है। यह गठबंधन एक साझेदारी है, जिसमें सरकारें, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, बहुपक्षीय विकास बैंक, निजी क्षेत्र की संस्थाएं, वित्तपोषण तंत्र और ज्ञान संस्थान शामिल हैं। इसका उद्देश्य जलवायु और आपदा जोखिमों के प्रति बुनियादी ढाँचे की प्रणालियों के लचीलेपन को बढ़ाना है, जिससे सतत विकास सुनिश्चित हो सके।

उल्लेखनीय है कि 28 अगस्त, 2019 को कैबिनेट ने नई दिल्ली में इसके सहायक सचिवालय के साथ सीडीआरआई की स्थापना को मंजूरी दी और वित्तीय सहायता के लिए 2019-20 से 2023-24 तक 5 वर्षों की अवधि में सीडीआरआई को रु. 480 करोड़ भी मंजूरी दी। इस शुरूआत के बाद से, 31 देश, 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन और दो निजी क्षेत्र के संगठन सीडीआरआई के सदस्य बन गए हैं। सीडीआरआई आर्थिक रूप से उन्नत देशों, विकासशील देशों और जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील देशों को आकर्षित करके लगातार अपनी सदस्यता का विस्तार कर रहा है। अपने प्रारंभिक चरण में, सीडीआरआई पारिस्थितिक, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के लचीलेपन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। बाद वाली श्रेणी परिवहन, ऊर्जा, दूरसंचार और जल प्रणालियों को प्राथमिकता देगी, जबकि सामाजिक बुनियादी ढांचे के भीतर स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी जोर देगी।

इन वर्षों में, गठबंधन का लक्ष्य सदस्य देशों में महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव लाना, लचीले बुनियादी ढांचे के निवेश को प्रोत्साहित करना और जलवायु से संबंधित घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान को काफी हद तक कम करना है।

आपदा प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

- भारत में पहली बार 23-26 नवंबर, 2015 में सार्क आपदा प्रबंधन अभ्यास (एसएडीएमईएक्स) आयोजित किया गया था।
- 5 अक्टूबर, 2015 को भारत-जर्मन संयुक्त आशय घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए।
- आपदा प्रबंधन पर ब्रिक्स सम्मेलन 2016 में उदयपुर में आयोजित किया गया।
- 03-05 नवंबर, 2016 को नई दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (एएमसीडीआरआर) पर 41 एशिया और एशिया प्रशांत देशों का एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) पर 10 सूत्री एजेंडे की घोषणा की।
- आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए जापान के साथ 12 सितंबर, 2017 को एक सहयोग ज्ञापन (एमओसी) पर हस्ताक्षर किए गए।
- भारत सरकार ने सामूहिक तैयारियों में सुधार के लिए 4-7 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य राज्यों का एक संयुक्त शहरी भूकंप खोज और बचाव अभ्यास आयोजित किया।
- केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह की अध्यक्षता में आपातकालीन स्थितियों की रोकथाम और उन्मूलन से संबंधित शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य-राज्यों के विभागों के प्रमुखों की दसवीं बैठक 8 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।
- ताजिकिस्तान गणराज्य की सरकार के साथ 8 अक्टूबर, 2018 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ■

देशप्रेम की बनी मिसाल

देश को महान बनाने को समर्पित होंगे आने वाले 25 साल

हाथ में तिरंगा लेकर खड़े हजारों लोगों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा देश के हर बच्चे और हर युवा के मन में देशभक्ति का जज्बा पैदा करने के लिए चलाया गया अभियान सफल हो रहा है। श्री शाह ने कहा कि हर घर तिरंगा यात्रा के तहत गुजरात से मिट्टी और तिरंगा हाथ में लेकर युवा दिल्ली के लिए निकले।

हमारे पूर्वजों ने देश की स्वतंत्रता के लिए जो बलिदान दिया है, वह सिर्फ बलिदान नहीं है बल्कि हमारे और आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन जीने का एक संस्कार है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर आकाश में फहराते करोड़ों तिरंगे भारत को फिर से महान बनाने की इच्छाशक्ति के प्रतीक हैं।

श्री अमित शाह ने सभी नागरिकों से निवेदन किया कि अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार सन 1857 से 1947 तक के 90 सालों में युवा पीढ़ी ने आजादी के आंदोलन का नेतृत्व किया और देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त किया, उसी तरह हमारी युवा पीढ़ी को 2023 से 2047 तक का समय देश को महान बनाने के लिए भारत माता को समर्पित करना है। लाखों-करोड़ों स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष और जीवन बलिदान करके देश को आजाद कराया । पिछले 75 सालों से हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर सारे विश्व में अपना रास्ता बना रहा है।

श्री शाह ने कहा कि युवाओं के उत्साह और उमंग को देखकर उन्हे पूरा विश्वास है कि यह अभियान जन-जन में और विशेषकर बच्चों और युवाओं में देश को महान बनाने के संकल्प को दृढ़ता के साथ स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव में समग्र देश में देशभक्ति का एक ज्वार खड़ा करने का काम किया है। 15 अगस्त,2023 को आजादी का अमृत महोत्सव पूरा होने के बाद प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 15 अगस्त 2023 से लेकर 15 अगस्त 2047 तक देश आजादी का अमृत काल मनाएगा। इस दौरान देश हर क्षेत्र में महान और अग्रणी बनेगा। ■

ब्यूरो

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित तिरंगा यात्रा में हिस्सा लेते हुए कहा 'आजादी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 से 1947 में आजादी मिलने तक के 90 वर्षों में युवा पीढ़ी ने आजादी के आंदोलन का नेतृत्व किया। इसी के बल पर देश गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो सका। उसी तरह वर्तमान की युवा पीढ़ी को 2023 से 2047 तक का समय देश को महान बनाने के लिए भारत माता को समर्पित करना है।' उन्होंने सभी देशवासियों से कहा 'हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता के लिए जो बलिदान दिया है वो सिर्फ बलिदान नहीं है, बल्कि हमारे लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन जीने का एक संस्कार है।'श्री शाह अहमदाबाद में आयोजित समारोह में बोल रहे थे। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से 'आजादी का अमृत महोत्सव' देशभक्ति का एक ज्वार खड़ा करने का जरिया बना, उसी तरह से 'मेरी माटी-मेरा देश' कार्यक्रम आने वाले दिनों में महान, विकसित व आत्मनिर्भर भारत बनाने के हमारे संकल्प को पूरा करेगा।

हर भारतीय का विश्वास

> सबका साथ, सबका विश्वास हमारे लिए एक नारा ही नहीं है, बल्कि यह विश्वास का प्रतीक है और एक प्रतिबद्धता है। मैं देश की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि शरीर का कण-कण और क्षण-क्षण देशवासियों की सेवा में समर्पित करूंगा।
>
> -श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने दिया जवाब

ब्यूरो

बीते कुछ वर्षों में सरकार विकसित भारत की मजबूत नींव रखने में सफल रही है। यही वह आधार है, जो वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में इसका नेतृत्व करेगा। भारत एक साथ मिलकर ही बदतर स्थितियों से बाहर आया है। स्वयं प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने सभी से आग्रह किया है कि वे संकीर्ण राजनीति के लिए मणिपुर की भूमि का दुरुपयोग न करें। प्रधानमंत्री ने अपील करते हुए कहा कि हमें दर्द तथा पीड़ा के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए और इससे उबरने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। उन्होंने इसे ही आगे बढ़ने का रास्ता बताया।

प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो भारत के युवाओं के सपनों को, उनकी महत्वाकांक्षाओं को, उनकी आशा अपेक्षा के मुताबिक, वो जो काम करना चाहता है, उसके लिए हम उसे अवसर दें। सरकार में रहते हुए हमने भी इस दायित्व को निभाने का भरपूर प्रयास किया है। भारत के युवाओं को घोटालों से रहित सरकार दी है। भारत के युवाओं को, आज के हमारे प्रोफेशनल्स को खुले आसमान में उड़ने के लिए हौसला दिया है, अवसर दिया है। दुनिया में भारत की बिगड़ी हुई साख उसको भी संभाला है और उसे फिर एक बार नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं। अभी भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में हमारी साख को दाग लग जाए, लेकिन दुनिया अब देश को जान चुकी है, दुनिया के भविष्य में भारत की किस प्रकार से योगदान दे सकता है, ये विश्व का विश्वास बढ़ता चला जा रहा है, हमारे ऊपर।

10 अगस्त, 2023 को जब लोकसभा में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सदन को प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने बीते नौ वर्षों में

लोकसभा में मणिपुर को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। जब प्रधानमंत्री ने सदन में अपना वक्तव्य दिया तो स्पष्ट शब्दों में केंद्र सरकार की मंशा और हर नागरिक के बढ़ते विश्वास को बताया। उनके अनुसार, पूर्वोत्तर आज भले दूर लगता हो, लेकिन जिस प्रकार से साउथ ईस्ट एशिया का विकास हो रहा है, जिस प्रकार आसियान देशों का महत्व बढ़ रहा है, वो दिन दूर नहीं होगा, हमारे पूर्व की प्रगति के साथ-साथ पूर्वोत्तर वैश्विक दृष्टि से विकास की धुरी केंद्र बनने वाला है। इसलिए सरकार पूरी ताकत से इस क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रही है।

केंद्र सरकार के कार्यों की पूरी जानकारी दी। कई अहम मंत्रालयों द्वारा किए गए जनहित के कार्यों के परिणाम की चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र आने वाले दिनों में विकास का केंद्र बनने वाला है। सरकार ने पूर्वोत्तर के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। श्री मोदी ने पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे में निवेश के बारे में उल्लेख किया और बताया कि कैसे आधुनिक राजमार्ग, रेलवे तथा हवाई अड्डे पूर्वोत्तर की पहचान बन रहे हैं। अगरतला पहली बार रेल कनेक्टिविटी से जुड़ा है, मालगाड़ी पहली बार मणिपुर पहुंची है, पहला अवसर रहा है जब वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेन इस क्षेत्र में चली

है, अरुणाचल प्रदेश में पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाया गया, सिक्किम को हवाई यात्रा से जोड़ा गया है, पहली बार पूर्वोत्तर में एम्स खोला गया है, मणिपुर में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय तथा मिजोरम में भारतीय जनसंचार संस्थान को खोला जा रहा है, पहला मौका है जब मंत्रिपरिषद में पूर्वोत्तर की भागीदारी बढ़ी है और पहली बार किसी महिला ने राज्यसभा में नागालैंड का प्रतिनिधित्व किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली बार पूर्वोत्तर के इतने सारे लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया और लचित बोरफुकन जैसे नायक को गणतंत्र दिवस पर सम्मान के साथ याद किया गया तथा रानी गाइदिन्ल्यू के नाम से एक संग्रहालय की स्थापना की गई।

सांसदों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि राष्ट्र की विकास यात्रा में एक समय ऐसा आता है, जब वह पुरानी बेड़ियों से मुक्त होकर नई ऊर्जा व दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ता है। 21वीं सदी का यह समय हमारी सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का वक्त है। इस समयावधि में देश जिस तरह का भी स्वरुप लेगा उसका प्रभाव इस पर अगले हजार वर्षों तक पड़ेगा। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि ऐसी स्थिति में हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हम सभी के ध्यान में एक ही केंद्र बिंदु-राष्ट्र के विकास और देशवासियों के सपनों को साकार करने के लिए पूर्ण समर्पण होना चाहिए।

हमने युवाओं को घोटालों से रहित सरकार दी है। दुनिया में भारत की बिगड़ी हुई साख को संभाला है। अभी भी कुछ लोग कोशिश में हैं कि साख को दाग लग गए। विश्व का विश्वास भारत में बढ़ता चला जा रहा है। भारत ने आतंकवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया। कोरोना की महामारी आई, भारत के वैज्ञानिकों ने मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाई। प्रधानमंत्री ने विपक्ष के अविश्वास पूर्ण रवैये का उल्लेख करते हुए स्वच्छ भारत, जनधन खाता, योग, आयुर्वेद, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों में उनके विश्वास की कमी के बारे में भी बताया। प्रधानमंत्री ने इस तथ्य को रेखांकित किया कि भारत अतीत में किस तरह से गरीबी में डूब गया था और 1991 में दिवालिया होने की कगार पर था। हालांकि, वर्ष 2014 के बाद भारत को दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में जगह मिली है। उन्होंने कहा कि यह लक्ष्य चरणबद्ध योजना और कड़ी मेहनत के साथ ही 'सुधार, प्रदर्शन एवं परिवर्तन' के मंत्र के माध्यम से हासिल किया गया था। विकास का यह सिलसिला जारी रहेगा और आवश्यक सुधार किये जायेंगे। आईएमएफ अपने एक वर्किंग पेपर में लिखता है कि भारत ने अति गरीबी को करीब-करीब खत्म कर दिया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में आम नागरिकों का विश्वास नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है और हर भारतीय आत्मविश्वास से भरा हुआ है। आज का भारत दबाव में नहीं ढहता। आज का भारत न झुकता है, न थकता है और न ही रुकता है। श्री मोदी ने नागरिकों से विश्वास एवं संकल्प के साथ आगे बढ़ने का आग्रह किया और कहा कि यह आम लोगों का विश्वास ही है, जो दुनिया को भारत पर भरोसा करने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने भारत पर दुनिया के बढ़ते विश्वास का श्रेय आम नागरिकों में बढ़ते भरोसे को दिया। देश की जनता को सरकार के प्रति विश्वास की बात करते हुए प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि बीते वर्षों में विकसित भारत की मजबूत नींव रखने में हम सफल हुए और संकल्प लिया है 2047 जब देश आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, आजादी के 75 वर्ष पूरे होते ही अमृतकाल शुरू हुआ है। हम अमृतकाल के प्रारंभिक वर्षों में है तब इस विश्वास के साथ मैं कहता हूं जो नींव आज मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है, उस नींव की ताकत है कि 2047 में हिन्दुस्तान विकसित हिन्दुस्तान होगा, भारत विकसित भारत होगा साथियों। और यह देशवासियों के परिश्रम से होगा, देशवासियों के विश्वास से होगा, देशवासियों के संकल्प से होगा, देशवासियों की सामूहिक शक्ति से होगा, देशवासियों की अखंड पुरुषार्थ से होने वाला है, यह मेरा विश्वास है।■

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि जल जीवन मिशन के जरिए भारत में चार लाख लोगों की जान बच रही है। चार लाख कौन हैं- मेरे गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित परिवारों के मेरे स्वजन हैं। हमारे परिवार के निचले तबके में जिंदगी गुजारने के लिए जो मजबूर हुए, ऐसे जन है, ऐसे चार लाख लोगों की जान बचा ने की बात विश्व स्वास्थ्य संगठन कह रहा है। एनालिसेस करके कहता है कि स्वच्छ भारत अभियान से तीन लाख लोगों को मरने से बचाया गया है।

-श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

विशेष बातें

- हमने भारत के युवाओं को घोटालों से मुक्त सरकार दी है।
- आज निर्धन के मन में भी अपने सपनों को पूरा करने का विश्वास पैदा हुआ है।
- महिलाओं के खिलाफ अपराध अस्वीकार्य हैं और केंद्र तथा राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य करेंगी कि दोषियों को सजा अवश्य मिले।
- मणिपुर में शांति स्थापित होगी और राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा।
- मैं मणिपुर के लोगों को, मणिपुर की माताओं एवं बेटियों को विश्वास दिलाता हूं कि देश आपके साथ है और पूरा सदन आपके साथ खड़ा है।
- हमारी सरकार ने पूर्वोत्तर के विकास को पहली प्राथमिकता दी है।
- सबका साथ, सबका विश्वास हमारे लिए एक नारा ही नहीं है बल्कि यह विश्वास का प्रतीक है और एक प्रतिबद्धता है।
- आज का हर भारतीय विश्वास से भरा हुआ है। आज का भारत न झुकता है, न थकता है और न रुकता है।

वामपंथी उग्रवाद की तोड़ी कमर

कश्मीर और पूर्वोत्तर में विकास का नया दौर

अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां

ब्यूरो

लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको साथ लेकर सरकार सबका विकास करने के लिए योजनाएं बनाती और उसको क्रियान्वित करती है। बीते नौ वर्षों में प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार के तमाम विभागों ने बेहतर काम किया है। जनता का सरकार पर भरोसा पहले से अधिक हुआ है। कई सर्वेक्षणों में इस बात का उल्लेख हुआ। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत खूबियों को बताया और जनता का उनके प्रति विश्वास का भी उल्लेख किया।

लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान अपने संबोधन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि देश की जनता ने 30 साल के बाद देश में पहली बार पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार देने का काम लगातार दो बार किया है। दुनिया भर के कई सर्वेक्षण कहते हैं कि श्री नरेन्द्र मोदी आजादी के बाद से अब तक देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं। आजादी के बाद बिना कोई छुट्टी लिए 24 में से 17 घंटे काम करने वाले और देश के हर राज्य में सबसे अधिक यात्रा और सबसे अधिक दिन प्रवास करने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं।

श्री अमित शाह ने साफ शब्दों में कहा कि मणिपुर में हो रही हिंसा से कोई सहमत नहीं हो सकता है और इन घटनाओं का कोई समर्थन नहीं कर सकता है, लेकिन इन घटनाओं पर राजनीति करना और अधिक शर्मनाक है। उन्होंने बताया कि पिछले 6 साल में मणिपुर में एक भी दिन कर्फ्यू, बंद और ब्लॉकेड नहीं हुआ और उग्रवादी हिंसा लगभग

> **सरकार ने 9 सालों में 50 से अधिक ऐसे फैसले किए हैं, जो युगांतकारी हैं। जिन्हें इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। आजादी के बाद बिना कोई छुट्टी लिए और 24 में से 17 घंटे काम करने वाला और देश के हर राज्य में सबसे अधिक यात्रा और सबसे अधिक दिन तक प्रवास करने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी हैं।**
>
> **-श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**

समाप्त हो गई है। हमने तीन दिन लगातार काम किया है, 16 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की 36,000 सुरक्षाबलकर्मी मणिपुर पहुंचाए गए, वायु सेना के विमानों का उपयोग किया गया, सुरक्षा सलाहकार को भेजा गया। केंद्रीय गृह मंत्री ने बताया कि वे स्वयं यूनिफाइड कमांड के साथ हर हफ़्ते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करते हैं, गृह सचिव हर दूसरे दिन और इंटेलीजेंस ब्यूरो के निदेशक प्रतिदिन सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 2014 से 2023 के 9 सालों में एक नए युग की शुरूआत की है। देश को स्थिर शासन दिया है इसीलिए

देश विकास कर रहा है। पिछले 9 सालों में शुरू किए गए नए युग से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कल्पना के भारत का निर्माण 2047 से बहुत पहले हो जाएगा।

भ्रष्टाचार पर लगाम

सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचा है। देश के करोड़ों गरीबों, दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्ग के लोगों के घरों में शुद्ध पीने का पानी नहीं था, लेकिन हर घर नल योजना के तहत 12.65 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाने का काम किया है। सरकार ने देश के साढ़े 14 करोड़ किसानों के बैंक खातों में ₹2.40 लाख करोड़ भेजने की व्यवस्था की, जिससे उन्हें कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देश में लगभग 50 करोड़ लोग ऐसे थे, जिन्हें बीमारी के दौरान इलाज के खर्च की चिंता होती थी, 50 करोड़ लोगों के लिए ₹5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्च माफ कर दिया। 49.65 करोड़ बैंक खाते खोले गये जिनमें ₹2 लाख करोड़ गरीबों के जमा हैं तथा केन्द्र और राज्य सरकारों की 300 से अधिक योजनाओं का पैसा डीबीटी के माध्यम से सीधे जन-धन खातों में ट्रांस्फर होता है। बिना किसी कमीशन या भ्रष्टाचार के ₹25 लाख करोड़ देश के गरीबों के बैंक खातों में सीधे ट्रांस्फर हुए हैं।

जम्मू-कश्मीर में शुरू हुआ विकास

90 के दशक के बाद पहली बार आज जम्मू-कश्मीर पुलिस एक्टिव होकर आतंकवाद का सामना कर रही है और जम्मू में नई हाई सिक्योरिटी जेल बनाई गयी है। जम्मू-कश्मीर में टूरिज्म के क्षेत्र में भी विकास हुआ है। साल 2022 में 1 करोड़ 80 लाख टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आए। सरकार जम्मू-कश्मीर में होम स्टे नीति, टूरिज्म बढ़ाने के लिए फिल्म निर्माण नीति, हाउसबोट नीति और औद्योगिक नीति लेकर आई है और 20000 लोगों को नौकरी देने का काम किया है। सरकार के 9 सालों की तुलना की जाए, तो जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं में 68% की कटौती, नागरिकों की मृत्यु में 82% और सुरक्षाबलों की मृत्यु में 56% की कमी हुई है।

वामपंथी उग्रवाद में कमी

भारत सरकार ने वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए इस पर नकेल कसी है। उन्होंने कहा कि 2005 -2014 में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा की घटनाओं की संख्या 14000, मृत्यु की संख्या 5790, हिंसाग्रत जिलों की संख्या 118, हिंसाग्रस्त पुलिस स्टेशन की संख्या 545 थी। वहीं 2014-22 में हिंसा की घटनाओं की संख्या 52% की कमी के साथ 6900, मृत्यु का आंकड़ा 69% की कमी के साथ 1811, हिंसाग्रत जिले 45 और हिंसाग्रत पुलिस स्टेशन 176 रह गये हैं।

उत्तर-पूर्व राज्यों में हिंसक घटनाएं हुई कम

प्रधानमंत्री पिछले 9 सालों में 50 से अधिक बार नॉर्थईस्ट गए हैं, ये बताता है कि नॉर्थईस्ट इस देश का हिस्सा है। श्री अमित शाह ने कहा कि पिछली सरकार के समय नॉर्थईस्ट में हिंसक घटनाएं 10 हजार, हताहत सुरक्षाबलों की संख्या 397 और नागरिकों की मृत्यु की संख्या 2298 थी जबकि मोदी सरकार के 9 सालों में हिंसक घटनाएं 68% की कमी के साथ 3238, हताहत सुरक्षाबलों की संख्या 68% की कमी के साथ 128 और नागरिकों की मृत्यु की संख्या 82% की कमी के साथ 420 हो गयी है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने यह भी बताया कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया देश को तोड़ने, देश की जनसांख्यिकी बदलने और आतंकवाद के बीज बोने का काम कर रही थी, इसलिए सितंबर, 2022 में एक ही दिन में 15 राज्यों में 90 से ज्यादा स्थानों पर रेडकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगाया गया। गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम के तहत 56 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया गया है। ■

भाषण के मुख्य बिंदु

- **पिछले 6 सालों में मणिपुर में एक भी दिन कर्फ्यू, बंद, ब्लॉकेड नहीं हुआ और उग्रवादी हिंसा लगभग समाप्त हो गई।**
- **लगभग 30 सालों से इस देश की राजनीति भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण के नासूर से ग्रसित रही। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण को हटाकर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को तरजीह दी है और आज विकास, जनता के फैसलों का निर्णय करता है।**
- **कोरोनाकाल में सरकार ने संघवाद की भावना से सबको साथ लेकर महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, भारत में कोरोना के खिलाफ केन्द्र, राज्य सरकारों और 130 करोड़ जनता ने एकसाथ लड़ाई लड़ी।**
- **गरीब घर से, संघर्ष करके राजनीति में आए सफल मुख्यमंत्री बनने वाले श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 9 सालों में देश के अर्थतंत्र को दुनिया में 11वें से 5वें स्थान पर पहुंचाने का काम किया है।**
- **कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद और पूर्वोत्तर तीन हॉटस्पॉट हैं, कश्मीर में हमारी नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। भारत सरकार ने 2014 से सातत्यपूर्ण ढंग से कश्मीर को आतंकवाद से मुक्त कराने का काम किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पिछली सरकारों की भूल सुधारते हुए 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाने का युगान्तकारी निर्णय लिया और कश्मीर से दो निशान, दो विधान को खत्म किया।**
- **आज झारखंड, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो चुके हैं और छत्तीसगढ़ के केवल तीन जिले शेष बचे हैं।**
- **प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2014 से गृह मंत्रालय ने नारकोटिक्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 1 लाख 65 हजार किलोग्राम नारकोटिक्स को जलाया गया जो कि आजादी के अमृत महोत्सव के एक वर्ष में अब 10 लाख किलोग्राम तक पहुंच गया है।**

संघीय व्यवस्था सहित भ्रष्टाचार मुक्त शासन के लिए जरूरी कदम

ब्यूरो

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बीते नौ वर्षों से भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था के लिए अपनी प्रतिबद्धता को बार-बार दोहराती आ रही है। हर परिस्थिति में पूरी पारदर्शिता के साथ जनता के हितों की रक्षा के लिए शासन व्यवस्था चलाने के लिए कहा गया है। केंद्रीय गृह एवं सहाकारिता मंत्री, श्री अमित शाह भी हर समय इसी बात को दोहराते रहते हैं। 8 अगस्त, 2023 को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य शासन संशोधन विधेयक 2023 यानी दिल्ली सर्विस बिल राज्यसभा में रखा गया और उस पर बातें हुईं, तो उन्होंने केंद्र सरकार का पक्ष पूरे देश के सामने रखा। मई में, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 जारी किया था, जिससे उच्चतम न्यायालय के उस फैसले का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र प्रशासन में 'सेवाओं' का नियंत्रण दिल्ली सरकार को दिया गया था।

राज्यसभा में बिल पर चर्चा होने से पहले दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग पर अध्यादेश को कानून का रूप देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 विपक्षी दलों के बहिर्गमन के बीच लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया था। लोकसभा में बहस के जवाब में केंद्रीय गृह एवं सहाकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने कहा था कि विपक्षी दलों ने सदन में पारित किसी भी विधेयक पर बहस में हिस्सा नहीं लिया। विपक्षी बेंचों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने तंज लहजे में सवाल किया था कि ऐसा क्या बदलाव आया है कि वे दिल्ली से संबंधित विधेयक में भाग ले रहे हैं? लोकसभा में श्री अमित शाह ने कहा था कि कुछ लोगों ने कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का उलंघन किया गया है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि उन्होंने केवल वही पढ़ा है, जो उन्हें अच्छा लगता है। आगे पढ़ा ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अपने आदेश में ही है कि संसद में दिल्ली राजधानी क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बनाया जा सकता है।

> **दिल्ली की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बिल लाया गया है। इस बिल का मकसद भ्रष्टाचार को रोकना है। इसके उद्देश्य संविधान के मुताबिक ही है। इस बिल का कोई भी प्रावधान संविधान का उल्लंघन नहीं करते।**
>
> **-श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**

दिल्ली की जनता के हितों की रक्षा की बात करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने साफ शब्दों में कह दिया कि इस बिल का मकसद है कि दिल्ली में भ्रष्टाचार विहीन शासन हो। हमें शक्ति लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि 130 करोड़ जनता ने हमें शक्ति दी हुई है। ये बिल हम शक्ति केंद्र में लाने के लिए नहीं, बल्कि केंद्र की दी हुई शक्ति पर दिल्ली की सरकार जो अतिक्रमण करती है, उसको वैधानिक रूप से रोकने के लिए लेकर लाए हैं।

श्री अमित शाह ने कहा कि सदन जनता को गुमराह करने की जगह नहीं है। अनुच्छेद 239 (एए)(3)(बी) के तहत संसद को केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली या उसके किसी भी हिस्से के संबंध में और उससे संबंधित किसी भी मामले पर कानून बनाने की पूरी शक्ति है। वर्ष 1993 से 2015 तक स्थापित नियमों के अनुसार सेवाएँ केंद्र सरकार के नियंत्रण में थीं। 1993 से 2015 तक दिल्ली में जो भी सरकार रही उसका लक्ष्य जनता की सेवा करना था और अगर सेवा करनी है, तो झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार को कानून बनाने का भी अधिकार है, नियम बनाने का भी अधिकार है। उन्होंने कहा कि नियम बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि दिल्ली में शासन नियमों के मुताबिक नहीं चल रहा है।

लोकतंत्र में लोक सबसे महत्वपूर्ण है। दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त है। संघीय व्यवस्था को पहले की तरह बनाए रखने और राष्ट्रीय राजधानी की सुचारू व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार ने संसद में राष्ट्रीय राजधानी राज्य शासन संशोधन विधेयक 2023 लाया, जिसे राज्यसभा में पास कर दिया गया।

श्री अमित शाह ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य शासन संशोधन विधेयक 2023 का उद्देश्य बताते हुए कहा कि इस बिल का उद्देश्य दिल्ली में सुचारू रूप से भ्रष्टाचार मुक्त शासन हो। बिल के एक भी प्रावधान से, पहले जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में एक इंच मात्र भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। चर्चा का जवाब देते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि यह विधेयक उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन नहीं करता है। दिल्ली में 2015 से पहले भाजपा और कांग्रेस की सरकार रही थी, लेकिन तब केंद्र के साथ कभी टकराव नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने भी अपने फैसले में कहा था कि केंद्र सरकार दिल्ली से संबंधित कानून बना सकती है। दिल्ली अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से भिन्न है, क्योंकि यह राष्ट्रीय राजधानी है और यहां संसद, उच्चतम न्यायालय और दूतावास स्थित हैं।

चर्चा के दौरान कई बार केंद्र सरकार और इस बिल पर कटाक्ष किया गया। इसको सधे हुए शब्दों में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने जबाव दिया और कहा कि शब्दों के श्रृंगार से असत्य को सत्य नहीं बनाया जा सकता। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी के सुंदर, लंबे शब्दों को बोलने से असत्य को सत्य नहीं बनाया जा सकता।

राज्यसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 पर चर्चा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से जवाब दिया गया था। उसके बाद इस बिल पर मतदान हुई। विपक्षी नेताओं की ओर से प्रस्तावित किए गए सभी संशोधन ध्वनिमत से नकार दिए गए। बिल पर हुए मतदान में पक्ष में 131 और विपक्ष में 102 वोट पड़े। इसी के साथ बिल को राज्यसभा से मंजूरी मिल गई। उसके बाद राष्ट्रपति ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए और अब यह कानून के रूप में अस्तित्व में आ गया है। ■

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य शासन संशोधन विधेयक 2023 की खास बात

- विधेयक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना करता है, जिसमें मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्य सचिव, दिल्ली के प्रधान गृह सचिव शामिल होते हैं। प्राधिकरण अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग और अनुशासनात्मक मामलों के संबंध में उपराज्यपाल को सिफारिशें करेगा।
- अनुच्छेद 239 (अअ)(3)(इ) के तहत संसद को दिल्ली संघराज्य क्षेत्र या इसके किसी भी भाग के बारे में और उससे संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।
- इस विधेयक में धारा 3 ए को भारत सरकार ने खुद ही हटा लिया है, अब दिल्ली की विधानसभा भी सेवा संबंधित नियम बना सकेगी, लेकिन वो कानून केन्द्र द्वारा बनाए गए कानून का विरोधाभासी नहीं होगा।
- इस विधेयक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में संशोधन का प्रावधान है।
- प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण के संबंध में दिल्ली सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद, राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 लागू किया।
- अध्यादेश का उद्देश्य 'सेवाओं के प्रशासन की एक व्यापक योजना प्रदान करना' है, जो भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से प्रतिबिंबित पूरे देश की लोकतांत्रिक इच्छा के साथ दिल्ली के लोगों के स्थानीय और घरेलू हितों को संतुलित करता है।
- बिल का उद्देश्य दिल्ली में भ्रष्टाचाररहित और लोकाभिमुख शासन सुनिश्चित करना है, बिल के किसी भी प्रावधान से पहले से चली आ रही व्यवस्था में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होगा।
- राज्यसभा में विधेयक के पक्ष में 131 सांसदों ने जबकि विपक्ष में 102 सांसदों ने वोट किया।

राजकोट को मिला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उपहार

ब्यूरो

27 जुलाई का दिन न केवल राजकोट, बल्कि पूरे सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इस दिन यहां प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के राजकोट में राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और 860 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। परियोजनाओं में सौनी योजना लिंक 3 पैकेज 8 और 9, द्वारका ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता (आरडब्ल्यूएसएस) का उन्नयन, ऊपरकोट किले का संरक्षण, पुनर्स्थापन कार्य और विकास, चरण I और II; जल शोधन संयंत्र, सीवेज शोधन संयंत्र और फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण आदि शामिल हैं। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को कुल 2500 एकड़ से अधिक भूमि क्षेत्र और ₹1400 करोड़ से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। नए हवाई अड्डे में आधुनिक तकनीक और स्थायी सुविधाओं का मिश्रण है। टर्मिनल भवन गृह-4 (एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए ग्रीन रेटिंग) के अनुरूप है और नया टर्मिनल भवन बिल्डिंग (एनआईटीबी) दोहरा अवरोध छत प्रणाली, स्काईलाइट्स, एलईडी लाइटिंग, निम्न ताप अवशोषण परावर्तन, जैसी विभिन्न सतत सुविधाओं से सुसज्जित है।

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने उद्घाटन किए गए नए राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का निरीक्षण किया। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री, श्री भूपेन्द्र पटेल, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, संसद सदस्य, श्री सी आर पाटिल, गुजरात सरकार के मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। खास है कि इस हवाई अड्डे से यात्रा में आसानी होने के अलावा, क्षेत्र के उद्योगों को भी काफी लाभ होगा। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस हवाई अड्डे के रूप में राजकोट को

देश भर में हवाई संपर्क में सुधार करने के प्रधानमंत्री के विजन को राजकोट में एक नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास से प्रोत्साहन मिला है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को कुल 2500 एकड़ से अधिक भूमि क्षेत्र और ₹1400 करोड़ से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। नए हवाई अड्डे में आधुनिक तकनीक और स्थायी सुविधाओं का मिश्रण है।

एक शक्ति-भंडार मिला है, जो इसे नई ऊर्जा और उड़ान देगा। हवाई अड्डे के टर्मिनल का डिजाइन राजकोट की सांस्कृतिक जीवंतता से प्रेरित है और यह अपने प्रभावी बाहरी अग्रभाग और शानदार आंतरिक सज्जा के माध्यम से लिप्पन कला से लेकर डांडिया नृत्य तक के कला रूपों को चित्रित करेगा। हवाई अड्डा स्थानीय वास्तुकला विरासत का प्रतीक होगा और गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र की कला और नृत्य रूपों के सांस्कृतिक गौरव को प्रतिबिंबित करेगा।

राजकोट का नया हवाई अड्डा न केवल राजकोट के स्थानीय ऑटोमोबाइल उद्योग के विकास में योगदान देगा, बल्कि पूरे गुजरात में व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्रों को भी प्रोत्साहन प्रदान करेगा। बता दें कि 2014 में सिर्फ 4 शहरों में मेट्रो नेटवर्क था, आज मेट्रो नेटवर्क भारत के 20 से ज्यादा शहरों तक पहुंच गया है। वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें 25 रेल-मार्गों पर चल रही हैं; इस अवधि के दौरान हवाई अड्डों की संख्या 2014 के 70 की तुलना में दोगुनी से भी अधिक हो गई। ■

प्रकृति के प्रति कटिबद्ध

हमारे महासागर दुनिया भर में तीन अरब से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करते हैं। विशेष रूप से 'छोटे द्वीप राष्ट्रों' के लिए ये एक महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन हैं, जिन्हें मैं 'बड़े महासागरीय राष्ट्र' कहता हूं। वे व्यापक जैव विविधता का घर भी हैं।

-श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

ब्यूरो

न तो नदियां अपना पानी खुद पीती हैं और न ही पेड़ अपने फल खाते हैं। बादल भी अपने पानी से पैदा होने वाले अनाज को नहीं खाते। पृथ्वी की रक्षा और देखभाल हमारी मौलिक जिम्मेदारी है और आज, जी20 की अध्यक्षता करते हुए भारत ने 'जलवायु कार्रवाई' को प्रमुखता से अपनी प्राथमिकताओं में शुमार किया है। भारत के पारंपरिक ज्ञान पर आधारित जलवायु कार्रवाई को 'अंत्योदय' का पालन करना चाहिए, जिसका अर्थ है समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान और विकास सुनिश्चित करना। यह देखते हुए कि ग्लोबल साउथ के देश विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय मुद्दों से प्रभावित हैं। 'संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन' और 'पेरिस समझौते' के तहत प्रतिबद्धताओं पर कार्रवाई बढ़ाने की आवश्यकता है। 28 जुलाई को जब पर्यावरण को लेकर जी20 की बैठक हुई तो प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने कई मुद्दों पर अपने विचार पूरी दुनिया के सामने रखे।

प्रधानमंत्री ने पिछले साल संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ पर्यावरण के लिए मिशन लाइफस्टाइल-मिशन लाइफ की शुरुआत को याद किया और कहा कि मिशन लाइफ एक वैश्विक जन आंदोलन के रूप में पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाई को प्रेरित करेगा। उन्होंने बताया कि हाल ही में घोषित 'ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम' के तहत अब ग्रीन क्रेडिट अर्जित किया जा सकता है। वृक्षारोपण, जल संरक्षण और टिकाऊ कृषि जैसी गतिविधियाँ अब व्यक्तियों, स्थानीय निकायों और अन्य लोगों के लिए राजस्व उत्पन्न कर सकती हैं।

प्रधानमंत्री ने जैव विविधता संरक्षण, सुरक्षा, बहाली और संवर्धन पर किए गए लगातार कार्यों पर प्रकाश डालते हुए टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत एक विशाल विविधता वाला देश है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि जंगल की आग और खनन से प्रभावित प्राथमिकता वाले परिदृश्यों की बहाली को 'गांधीनगर कार्यान्वयन रोडमैप और प्लेटफॉर्म' के माध्यम से मान्यता दी जा रही है। सात बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए हाल ही में लॉन्च किए गए 'इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस' का उल्लेख किया और एक अग्रणी संरक्षण पहल 'प्रोजेक्ट टाइगर' की सीख को श्रेय दिया। साथ ही यह भी बताया कि प्रोजेक्ट टाइगर के परिणामस्वरूप आज दुनिया के 70 प्रतिशत बाघ भारत में पाए जाते हैं। प्रधानमंत्री ने प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन पर चल रहे काम का भी जिक्र किया।

'मिशन अमृत सरोवर' का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने पूरी दुनिया के सामने यह बात रखी कि जो एक अनूठी जल संरक्षण पहल है, जहां लगभग एक वर्ष में 63,000 से अधिक जल निकाय विकसित किए गए हैं। मिशन को पूरी तरह से सामुदायिक भागीदारी और प्रौद्योगिकी की सहायता से लागू किया गया है। उन्होंने 'कैच द रेन' अभियान का भी जिक्र किया, जिसके तहत लगभग 2,50,000 पुनः उपयोग और पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के साथ-साथ जल संरक्षण के लिए 2,80,000 से अधिक जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया है। यह सब लोगों की भागीदारी और स्थानीय मिट्टी और पानी की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करके हासिल किया गया था। इसके साथ ही श्री नरेन्द्र मोदी ने गंगा नदी को साफ करने के लिए 'नमामि गंगे मिशन' में सामुदायिक भागीदारी का प्रभावी ढंग से उपयोग करने पर भी चर्चा की, जिसके परिणामस्वरूप नदी के कई हिस्सों में गंगा डॉल्फिन के फिर से प्रकट होने की बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। आर्द्रभूमि संरक्षण में रामसर साइटों के रूप में नामित 75 आर्द्रभूमियों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत में एशिया में रामसर साइटों का सबसे बड़ा नेटवर्क है।■

508 रेलवे स्टेशनों का होगा कायाकल्प

₹24,470 करोड़ की लागत से होगा आधुनिकीकरण

ब्यूरो

समाज के लिए अच्छा काम करने की इच्छा बहुतेरों में होती है, लेकिन विरले ही इसे पूरा कर पाते हैं। खासतौर से बड़े अच्छे काम के लिए किसी को आगे आना पड़ता है। ऐसा ही बीड़ा उठाया है प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने। पिछले नौ वर्षों में इन्होंने कई महत्वपूर्ण काम किए हैं और सभी ने पूर्णता का अमली-जामा पहना है। बीते 6 अगस्त को प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी इस क्रम को आगे बढ़ाया और एक और ऐतिहासिक काम किया। बात कर रहे हैं 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की। इसके लिए इन्होंने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिए इनकी आधारशिला रखी। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नया भारत, जो विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है, वह अमृत काल के उदय पर है।

देश के आर्थिक विकास को गति देने में रेलवे की भूमिका होती है। इस वर्ष रेलवे को ₹2.5 लाख करोड़ से अधिक का बजट मिला, जो 2014 की तुलना में पांच गुना अधिक है। यही वजह है कि आज समग्र दृष्टिकोण के साथ रेलवे के पूर्ण विकास के लिए काम किया जा रहा है। पिछले 9 वर्षों में लोकोमोटिव उत्पादन में 9 गुना की वृद्धि हुई है। आज 13 गुना अधिक एचएलबी कोचों का निर्माण किया जा रहा है।

शहरों की पहचान अपने रेलवे स्टेशनों से भी जुड़ी है, जो समय व्यतीत होने के साथ शहरों की केंद्रस्थली बन गए हैं। इससे स्टेशनों को आधुनिक स्वरूप प्रदान करना अनिवार्य हो गया है। इस बारे में प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि इतने सारे स्टेशनों के आधुनिकीकरण से देश में विकास के लिए एक नया वातावरण बनेगा, क्योंकि वे आगंतुकों के बीच एक अच्छी छाप छोड़ेंगे। अपग्रेड किए गए स्टेशनों से न केवल पर्यटन बढ़ेगा, बल्कि आस-पास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। अमृत स्टेशन भारत की सांस्कृतिक और स्थानीय विरासत की झलक प्रस्तुत करेंगे। प्रधानमंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा कि जयपुर रेलवे स्टेशनों पर राजस्थान के हवा महल और आमेर किले की झलक देखने को मिलेगी, जम्मू-कश्मीर का जम्मू तवी रेलवे स्टेशन प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर से प्रेरित होगा और नगालैंड का दीमापुर स्टेशन क्षेत्र की 16 विभिन्न जनजातियों की स्थानीय वास्तुकला को प्रदर्शित करेगा। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि प्रत्येक रेलवे स्टेशन प्राचीन विरासत के साथ-साथ देश की आधुनिक आकांक्षाओं का प्रतीक होगा। 'वन स्टेशन वन प्रोडक्ट' योजना कारीगरों की मदद करेगी और जिले की ब्रांडिंग में सहायता करेगी। 'नई ऊर्जा, नई प्रेरणा और नए संकल्प हैं' और यह भारतीय रेल के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरूआत है। देश के लगभग 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशनों को अब आधुनिकता के साथ 'अमृत भारत स्टेशन' के रूप में पुनर्विकसित किया जाएगा और उन्हें नया जीवन मिलेगा। इस पुनर्विकास परियोजना से रेलवे का तो भला होगा साथ ही आम नागरिकों को भी फायदा पहुंचेगा, क्योंकि ये आम नागरिकों के लिए भी देश में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक बड़ा अभियान होगा।

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी बताया कि उत्तर प्रदेश में लगभग ₹4,000 करोड़ की लागत से 55 अमृत स्टेशन विकसित किए जाएंगे और राजस्थान में भी 55 स्टेशन अमृत स्टेशन बनाएं जाएंगे, मध्य प्रदेश में लगभग ₹1,000 करोड़ की लागत से 34 स्टेशन, महाराष्ट्र में ₹1,500 करोड़ की लागत से 44 स्टेशन और तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में प्रमुख रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। अब भारतीय रेल को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाएगा। इसके तहत 100 प्रतिशत रेल लाइन विद्युतीकरण बहुत जल्द हासिल कर लिया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप भारत में सभी रेलगाड़ियां केवल बिजली से चलेंगी। सौर पैनलों से बिजली पैदा करने वाले स्टेशनों की संख्या पिछले 9 वर्षों में 1200 से अधिक हो गई है। केंद्र सरकार का लक्ष्य निकट भविष्य में प्रत्येक रेलवे स्टेशन से हरित ऊर्जा का उत्पादन करना है। फिलहाल लगभग 70,000 कोचों में एलईडी लाइटें लगाई गई हैं और 2014 की तुलना में ट्रेनों में जैव-शौचालयों की संख्या में 28 गुना वृद्धि हुई है। खात बात यह है कि 2030 तक, भारत एक ऐसा देश होगा जिसका रेलवे नेटवर्क शुद्ध शून्य उत्सर्जन पर चलेगा। बता दें कि लाइनों के दोहरीकरण, गेज परिवर्तन, विद्युतीकरण और नए मार्गों पर तेजी से काम चल रहा है। जल्द ही पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियां रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएंगी। नगालैंड को 100 वर्ष बाद अपना दूसरा स्टेशन मिला है। सकरात्मक बात है कि क्षेत्र में नई रेलवे लाइनों की कमीशनिंग में तीन गुना वृद्धि हुई है। ■

एक साल में 10 लाख किलोग्राम मादक पदार्थों को किया गया नष्ट

> नशे के खिलाफ यह लड़ाई न केवल ड्रग्स के कारोबार पर नकेल कसने और इस पर सम्पूर्ण विजय प्राप्त करने की है, बल्कि जागरूकता पैदा करना भी इसका उद्देश्य है। जब तक युवाओं के मन में नशे के खिलाफ जागरूकता पैदा नहीं होगी, तब तक ये लड़ाई सफल नहीं होगी।
>
> - श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

ब्यूरो

नशे की लत सिर्फ व्यक्ति को नहीं उसके परिवार, आनेवाली नस्लों को बर्बाद करती है। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा भी प्रभावित होती है। ऐसी बहुत सी बातें केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने 17 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित 'ड्रग तस्करी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा' पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करने के दौरान कही। इस सम्मेलन में पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और दिल्ली के उपराज्यपाल, ओडिशा के गृह राज्य मंत्री भी शामिल हुए। केंद्रीय गृह सचिव, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों व भारत सरकार के संबद्ध मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में उपस्थित थे। विशेष बात यह रही कि सम्मेलन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री की उपस्थिति में वर्चुअल रूप से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा सभी राज्यों के एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स के साथ समन्वय से देश के विभिन्न हिस्सों में ₹2,381 करोड़ मूल्य के 1 लाख 40 हजार किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थों को नष्ट किया गया, जो एक दिन में सर्वाधिक ड्रग नष्ट करने का रिकॉर्ड है।

प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह के नेतृत्व में आजादी के अमृत महोत्सव के पिछले एक साल में अब तक 10 लाख किलोग्राम मादक पदार्थों को नष्ट किया गया है। जिसका मूल्य लगभग ₹12,000 करोड़ है। यह भी एक रिकॉर्ड है। श्री अमित शाह ने बताया कि प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान देश के सामने लक्ष्य रखा है कि जब देश की आजादी की शताब्दी मनाई जाए तब तक भारत और इसके युवा नशामुक्त हो जाएं। सरकार का लक्ष्य है ऐसे भारत का सृजन करें, जिसमें देश का एक भी युवा में नशे की आदत ना हो। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए राज्यों और केंद्र दोनों को मिलकर काम करना जरूरी है।

आंकड़ों पर गौर करें, तो 2006 से 2013 के बीच कुल 1250 मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2014 से 2023 के 9 सालों में 3,700 मामले दर्ज हुए हैं, जो 200 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। पहले कुल 1,360 गिरफ्तारी हुई थी, जो अब 5,650 हो गई हैं, जो 300 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। जब्त ड्रग की मात्रा पहले 1.52 लाख किलोग्राम थी, जो अब 160 प्रतिशत बढ़कर 3.94 लाख किलोग्राम हो गई है। 2006 से 2013 के बीच ₹5,900 करोड़ के ड्रग को विनिष्ट किया गया था, 2014 से 2023 के बीच ₹18,100 करोड़ के ड्रग को पकड़कर विनिष्ट किया गया है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने कहा कि राज्यों को ड्रग के खिलाफ विशिष्ट अदालतें बनानी चाहिए और इसके प्रॉसीक्यूशन को फास्ट ट्रैक मोड में किया जाए। सजा जितनी ज्यादा होगी, इसकी रोकथाम में उतना ही फायदा होगा क्योंकि इससे एक कठोर संदेश जाता है। साथ ही नशीले पदार्थों के व्यापार में लिप्त लोगों की संपत्ति जब्ती के मामले भी बढ़ाने चाहिए। इन लोगों के सार्वजनिक बहिष्कार से ही बाकी लोग इस व्यापार से जुड़ने से रुकेंगे। बेरहमी से हमें संपत्ति की कुर्की की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। फोरेंसिक साइंस लैब को मजबूत करने के लिए जब तक हम काम नहीं करेंगे, प्रॉसीक्यूशन आगे नहीं बढ़ेगा। इसी प्रकार से अवैध खेती के विनिष्टीकरण के लिए भी, विशेषकर उत्तरी क्षेत्र में, इस क्षेत्र के मुख्यमंत्रियों को विशेष ध्यान देना चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ हमारा अभियान देश की आने वाली नस्लों को बचाने का पुण्य अभियान है, देश को सुरक्षित रखने का अभियान है और ये हम सबकी प्राथमिकता होना चाहिए। ■

केंद्रीय गृह मंत्री ने किया इंडो-पाक सीमा का दौरा

ब्यूरो

भारत पाकिस्तान सीमा के संवेदनशील इलाकों में गुजरात का कच्छ इलाका भी है। जहां करीब 22 किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र है, जिसका काफी हिस्सा पानी से डूबा हुआ ही है। एक बड़े भाग में दलदल (करीब आठ किलोमीटर में) चलना बेहद मुश्किल है। यहां एक ओर अगाध जलराशि और दूसरी ओर दलदली जमीन। प्रतिकूल माहौल के कारण इस क्षेत्र को 'हरामी नाला' के नाम से जाना जाता है। इस दलदली जमीन पर किसी प्रकार का निर्माण भी संभव नहीं है। यहां मौसम के साथ-साथ भौगोलिक स्थिति पल-पल बदलती रहती है। इसका एक हिस्सा राजस्थान के बाड़मेर को छूता है। समुद्र में ज्वार आने से दलदली जमीन का मिजाज और तमाम दूसरी चीजों की स्थिति बदलती रहती है। इस विषम परिस्थितियों के बीच इस क्षेत्र में किसी प्रकार की स्थायी निशानदेही मुश्किल हैं। पड़ोसी देश से होने वाले किसी भी घुसपैठ आदि को रोकने की पूरी जिम्मेदारी सीमा सुरक्षा बल की है, जिसका निर्वहन वे बखूबी करते हैं। दलदल वाली जमीन पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को गम बूट पहनकर चलना पड़ता है।

इस क्षेत्र को अभेद्य बनाने के लिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह के अथक प्रयास से विकास के कई काम शुरू किए गए हैं। इसमें एक आउटपोस्ट टॉवर 1164 का निर्माण कार्य भी है। लगभग साढ़े 9 मीटर ऊंचे इस टावर में अत्याधुनिक कैमरे लगे हैं, जो सीमापार होने वाली छोटी से छोटी मूवमेंट को भी कैप्चर कर हमारे सीमा प्रहरियों को सतर्क कर सकेंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि इस टॉवर के बनने से हमारी सीमा की सुरक्षा अभेद्य हो जाएगी। जवानों और अधिकारियों का हिम्मत बढ़ाने के लिए श्री शाह ने हरामी नाला का दौरा किया। जमीनी हालात देखकर यहां के लिए कई निर्देश दिए।

हरामी नाले पर दुश्मन निगरानी में चूक होने या खराब मौसम का फायदा उठाकर घुसपैठ करने की फिराक में रहते हैं। अब आउटपोस्ट टॉवर के बन जाने से किसी के लिए भी घुसपैठ करना आसान नहीं होगा। श्री शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल गुजरात के संवेदनशील तटीय क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्त्व से जुड़े अनेक संस्थानों की सुरक्षा सजगता व तत्परता से कर रही है।

श्री अमित शाह ने कहा कि देश के गृह मंत्री के नाते आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से देश की सीमाओं की सुरक्षा के बारे में वे निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि सीमा सुरक्षा बल के पास ये ज़िम्मेदारी है। उन्होंने कहा की सीमा सुरक्षा बल-43 डिग्री से लेकर+43 डिग्री तक अलग-अलग तापमान के बीच सीमाओं की सुरक्षा करती है। चाहे सुंदरवन हो, हरामी नाला हो, जम्मू और कश्मीर की बर्फ से ढकी पहाड़ियां हों या फिर कई प्रकार के जलप्रपातों से घिरा हुआ बांग्लादेश का बॉर्डर हो, सीमा सुरक्षा बल ने हमेशा अपनी नजर दुश्मन पर रखी है। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा बल के पास लगभग 450 से ज्यादा वाटर वेसेल्स हैं और यहां बनने वाली इस सुविधा से इनके रख-रखाव और सजगता को बनाए रखने में बहुत मदद मिलेगी। ■

हरामी नाला से जुड़े तथ्य

- 22 किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र है, जिसका काफी हिस्सा पानी से डूबा हुआ ही है।
- नाला में पानी के साथ-साथ बड़ी मात्रा में कीचड़ का बहाव रहता है।
- भारत के लिए बड़ी सुरक्षा चुनौती रहा है।
- केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने सुरक्षा चाक चौबंद करने के लिए उठाया बड़ा कदम।
- आउटपोस्ट टॉवर पर लगे कैमरों के जरिए दुश्मन की गतिविधियों पर रहेगी कड़ी नजर।

सीमाओं को अभेद्य बनाना हमारी प्राथमिकता

कच्छ में श्री अमित शाह ने विभिन्न परियोजनाओं का किया उद्घाटन

ब्यूरो

पड़ोसी देशों से सटी सीमाओं पर पूरी मुस्तैदी के साथ डटे रहने वाले सीमा सुरक्षा बल के जवानों व अधिकारियों को पहले से अधिक सहूलियत देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय समय-समय पर काम करता रहा है। इसी कड़ी में 12 अगस्त को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मत्री, श्री अमित शाह ने गुजरात के कच्छ में सीमा सुरक्षा बल के मूरिंग प्लेस का भूमि पूजन और विभिन्न परियोजनाओं का ई-लोकार्पण किया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह सचिव और महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल सहित अनेक गणमान्य भी शामिल होकर उपस्थित रहे। इस परियोजना के तहत लगभग ₹250 करोड़ की लागत से एक पूर्णाधिकृत प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स, ऑफिसर्स मेस, कैंटीन, परेड ग्राउंड, ट्रेनिंग सेंटर, जल यानों की मरम्मत और आपूर्ति के लिए वर्कशॉप सहित एक अत्याधुनिक यूनिट बनाई गई है। अपने संबोधन में उन्होंने कर्मियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि जवानों के समर्पण, त्याग और बलिदान को देश की 130 करोड़ की जनता बहुत सम्मान के साथ देखती है। सीमा सुरक्षा बल के पास जल, थल और आकाश तीनों की सुरक्षा करने का सामर्थ्य और हौसला है।

कर्मियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वन बॉर्डर, वन फोर्स का निर्णय लिया था। इस निर्णय के कारण हमारी बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज को भौगोलिक परिस्थितियों, सीमावर्ती देश के साथ हमारे राजनीतिक संबंधों और खतरों का मूल्यांकन करना बहुत आसान हो गया। उस समय सीमा सुरक्षा बल को पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी हुई सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई। इस निर्णय को लेने के पीछे बहुत गहरी सोच रही होगी, क्योंकि सीमा सुरक्षा बल की सजगता पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगती हुई सीमाओं के अनुरूप और इनकी सुरक्षा करने में सक्षम है। श्री शाह ने कहा कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में अकेला सीमा सुरक्षा बल ऐसा बल है, जिसके पास भूमि और जल सीमाओं की सुरक्षा करने की विशेषज्ञता है और इसका अपना एयर विंग भी है। ■

एनएएफआईएस के समर्पण का सम्मान

हौसला अफजाई जरूरी होती है आगे बढ़ने के लिए। इसके बाद काम में निखार निरंतर आता रहता है। कुछ ऐसा हुआ राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम (एनएएफआईएस) की टीम के साथ। इस टीम ने भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) की 'डिजिटल ट्रांस्फॉर्मेशन के लिए सरकारी प्रक्रिया री-इंजीनियरिंग' कैटेगरी-1 में गोल्ड अवॉर्ड जीता। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने ट्वीट करके इस टीम को बधाई दी। श्री शाह ने लिखा कि नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ने कुशल प्रशासन के शानदार उदाहरण के रूप में अपनी पहचान बनाई है क्योंकि इसने श्रेणी-1 में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग का स्वर्ण पुरस्कार जीता है।

भारतीय भाषाओं के प्रसार के लिए अनुकूल समय

ब्यूरो

जब देश के प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी हर वैश्विक मंच पर हिन्दी सहित अन्य भारतीय भाषाओं को गर्व से रखते हैं तो निश्चित तौर पर पूरी दुनिया में भारतीय भाषाओं का प्रचार-प्रसार बढ़ेगा।

प्रधानमंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में देश के सामने पांच प्रण रखे हैं, जिनमें से दो प्रण हैं–विरासत का सम्मान और गुलामी के चिन्हों को मिटाना। विरासत का सम्मान भाषा के सम्मान के बिना अधूरा है और राजभाषा की स्वीकृति तभी आएगी जब स्थानीय भाषाओं को सम्मान दिया जाएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह का कहना है कि हिन्दी की स्पर्धा स्थानीय भाषाओं से नहीं है, सभी भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने से ही राष्ट्र सशक्त होगा। उनका कहना है कि बिना किसी प्रकार के विरोध के राजभाषा की स्वीकृति बनाने की आवश्यकता है।

हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के तत्वावधान में राजभाषा विभाग काम करता है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री का मानना है कि एकता के सूत्र में मजबूती के साथ पिरोने के लिए एक भाषा का होना आवश्यक है। चूंकि यह भाषा हिंदी सर्वतोभावेन एक समर्थ भाषा है। इसलिए इसे जननेताओं एवं जनता ने स्वीकार किया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदी की यह स्वीकृति हिंदी क्षेत्र के लोगों की ही नहीं, हिंदीतर भाषी राजनेताओं, पत्रकारों तथा हिंदी प्रेमियों की भी थी। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार, संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी और उसके अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा का प्रसार, वृद्धि करना और उसका विकास करना ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, संघ का कर्तव्य है। हिंदी के प्रसार एंव विकास की गति बढ़ाने हेतु तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए उत्तरोत्तर इसके प्रयोग हेतु भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा और किए जाने वाले उपायों एवं की जाने वाली प्रगति की विस्तृत वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखी जाएगी और सब राज्य सरकारों को भेजी जाएगी।

संसदीय राजभाषा समिति की 38वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह का कहना है कि राजभाषा की स्वीकृति कानून या सर्कुलर से नहीं बल्कि सद्भावना, प्रेरणा और प्रयास से आती है। गुलामी के कालखंड के बाद भी भारतीय भाषाएं और उनके शब्दकोष अक्षुण्ण रहे, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। श्री शाह ने कहा कि भाषाओं ने हमारे देश को जोड़ने का काम किया है। बैठक में संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष, श्री भर्तृहरि महताब, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री, श्री अजय कुमार मिश्रा एवं श्री निशिथ प्रमाणिक और संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य उपस्थित थे।

इस अवसर पर श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने इंजीनियरिंग और मेडिकल के पाठ्यक्रमों को 10 भाषाओं में शुरू कर दिया है और जल्द ही ये सभी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होंगे और वह क्षण स्थानीय भाषाओं और राजभाषा के उदय की शुरुआत का क्षण होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाओं के प्रसार के लिए इससे अनुकूल समय कोई और नहीं हो सकता जब देश के प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी हर वैश्विक मंच पर हिन्दी सहित अन्य भारतीय भाषाओं को गर्व से रखते हैं। प्रधानमंत्री संसद में एक भी भाषण अंग्रेजी में नहीं देते और सरकार के मंत्री भी भारतीय भाषाओं में भाषण देने का प्रयास करते हैं। इससे अलग-अलग भाषाओं को जोड़ने के आंदोलन को बहुत गति मिलती है। ■

हर दिन क्रियाशील

ब्यूरो

दिल्ली के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन भवन में कनाडा में आयोजित होने वाले वर्ल्ड पुलिस एवं फायर खेल 2023 हेतु भारतीय पुलिस दल के प्रस्थान समारोह का आयोजन किया गया था। कनाडा के विन्निपेग में 28 जुलाई से आठ अगस्त तक वर्ल्ड पुलिस एण्ड फायर गेम्स 2023 का आयोजन हुआ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, श्री नित्यांनद राय इसी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

इस अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, श्री नित्यानंद राय ने कहा कि प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बीते 9 वर्षों में देश में खेलो इंडिया के माध्यम से टीम भावना बढ़ी है, साथ ही खेलों ने 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को जाग्रत करने का अभूतपूर्व काम किया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृहमंत्री हमेशा खेल एवं खिलाड़ियों को बढ़ावा मिले, इसके लिए प्रयास करते हैं। अंतरराष्ट्रीय खेलों में देश की सकारात्मक छवि को बनाए रखने में भारतीय पुलिस सदैव अग्रणी रही है और बीते वर्षों के प्रदर्शन को देखें तो उनके प्रदर्शन में निरंतर उल्लेखनीय प्रगति ही देखने को मिली है।

वर्ल्ड पुलिस एवं फायर खेल में जाने वाले पुलिस दल को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने अपनी शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर केंद्रीय गृह सचिव श्री अजय कुमार भल्ला भी उपस्थित थे।

सुरक्षा के साथ ही स्वास्थ्य की चिंता और जनता को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सरकार की ओर से लगातार काम किया जा रहा है। उसी कड़ी में 27 जुलाई को केंद्रीय गृह राज्यमंत्री, श्री अजय

केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत जो दायित्व दिया गया है, उसका निर्वहन गृह राज्य मंत्री कर रहे हैं। बैठक और सभाओं के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक नागरिक को मिले, इसके लिए प्रयत्नशील हैं।

मिश्रा ने लखीमपुर खीरी- महिला जिला चिकित्सालय में हेल्थ एटीएम एवं राजगढ़ में प्राथमिक स्वस्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया। इस दौरान उनका कहना था कि शहर में एक और नगरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के शुभारंभ से राजगढ़ मोहल्ले सहित शिव कॉलोनी, कंचन पुरी कॉलोनी, पंजाबी कॉलोनी, मोतीनगर कॉलोनी, राम नगर कॉलोनी सहित शहर के लोगों को और अधिक बेहतर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं मिलने लगेंगी। अब उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए यहां से 15 किलोमीटर दूर स्थित जिला पुरुष चिकित्सालय तक की यात्रा नहीं करनी होगी। जिला महिला चिकित्सालय में हेल्थ एटीएम की शुरुआत होने से गर्भवती माताओं और बच्चों को भी 98 जांचों का लाभ मिल पाएगा।

इसके साथ ही लखीमपुर खीरी में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का भी शुभारंभ किया गया और लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया।

दक्षिण अफ्रीका में हुए ब्रिक्स युवा मामलों के मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय गृह राज्य एवं युवा मामलों के मंत्री, श्री निशिथ प्रमाणिक ने किया। भारत का पक्ष रखते हुए उन्होंने सरकार के कामकाज को लेकर विस्तृत चर्चा की और एक साथ मिलकर उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए सार्थक चर्चा की। 21 जुलाई को श्री निशिथ प्रमाणिक ने दक्षिण अफ्रीका की मंत्री डॉ. नकोसाजाना दलामिनी जुमा के कार्यों की खूब प्रशंसा की। उनकी ओर से कहा गया कि ब्रिक्स सम्मेलन में आपसी संबंधों को लेकर गहन विचार-विमर्श किया गया।

ब्रिक्स पांच उभरती अर्थव्यवस्थाओं-ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का संक्षिप्त रूप है। दक्षिण अफ्रीका ने 1 जनवरी, 2023 को चीन से पदभार ग्रहण करते हुए ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण की। ■

श्री के.एम.सिंह

आपदा प्रबंधन में वैश्विक मानक स्थापित करने में सक्षम है भारत

मैंने भारत में आती प्राकृतिक आपदाओं को देखा हैं। वैसे भी प्राकृतिक आपदाएं दस्तक देकर नहीं आती। इसके लिए हमें तैयार रहना होता है। प्राकृतिक आपदाओं के इतिहास खंगालने से मालूम चलता है कि भारत में हिमालय के भूकंपों से लेकर बंगाल की खाड़ी के चक्रवातों के कई उदाहरण हैं। जैसे-जैसे हम जलवायु परिवर्तन और शहरी विस्तार के कगार पर खड़े हैं, वैसे-वैसे भारत में आपदा प्रबंधन की चुनौतियां तेजी से विकसित हो रही हैं।

अभी तक आपदा प्रबंधन के प्रति भारत का दृष्टिकोण प्रतिक्रियाशील रहा है। आपदा के बाद राहत प्रयास सराहनीय थे, लेकिन अकसर सक्रिय उपायों का अभाव था। यह बदलाव 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम के साथ गंभीरता से शुरू हुआ, जो तैयारियों, जोखिम में कमी और क्षमता निर्माण पर जोर देने के अलावा अधिक व्यवस्थित और संरचित प्रतिक्रिया की ओर बढ़ने का संकेत देता है।

2014 में प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार आने के बाद इस ओर बहुत काम हुआ है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि उन्होंने आपदा प्रबंधन प्रणालियों में नई ऊर्जा का संचार किया है। जिसमें आपदा से पहले ही सबको सचेत किया गया, ताकि आपदा से पहले ही बचाव और नुकसान को कम किया जा सके। यह आपदाओं का शमन का केंद्रबिंदु बन गया है।

इसे कहते हैं कुशल और सबके नेता, जो एक की नहीं सबकी सुनता है और उनकी समस्याओं का समाधान निकालता है। आपदा प्रबंधन की बाबत प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने इस ओर 10 सूत्रीय एजेंडे की घोषणा की है। जिसमें शामिल है, सभी विकास क्षेत्रों को आपदा जोखिम प्रबंधन के सिद्धांतों को अपनाना चाहिए, जोखिम कवरेज में गरीब से लेकर एसएमई तक व बहुराष्ट्रीय निगमों से लेकर राष्ट्र राज्यों तक सभी को शामिल करना चाहिए, महिलाओं का नेतृत्व और अधिक भागीदारी आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए केंद्रीय होना चाहिए, प्रकृति और आपदा जोखिमों की वैश्विक समझ को बेहतर बनाने के लिए विश्व स्तर पर जोखिम मानचित्रण में निवेश करना चाहिए, आपदा जोखिम प्रबंधन प्रयासों की दक्षता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना चाहिए, आपदा से संबंधित मुद्दों पर काम करने के लिए विश्वविद्यालयों का एक नेटवर्क विकसित करना चाहिए, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सोशल मीडिया और मोबाइल प्रौद्योगिकियों द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का उपयोग करें, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सोशल मीडिया और मोबाइल प्रौद्योगिकियों द्वारा प्रदान किए गए अवसरों का उपयोग करें, आपदा जोखिम न्यूनीकरण को बढ़ाने के लिए स्थानीय क्षमता और पहल का निर्माण करें, आपदाओं से सीखने के लिए हर अवसर का उपयोग करें और, इसे प्राप्त करने के लिए, प्रत्येक आपदा के बाद सबक पर अध्ययन होना चाहिए, आपदाओं के प्रति अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया में अधिक सामंजस्य लाना चाहिए। ये व्यापक दिशानिर्देश हैं जो भारत में आपदा प्रबंधन का स्तंभ बन गए हैं। कहना गलत नहीं होगा कि ये सभी एजेंडे भारत में आपदा प्रबंधन का स्तंभ बन गए हैं।

जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, कई बड़ी चुनौतियां हमारे सामने आती हैं। बढ़ते वैश्विक तापमान के साथ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के परिणामस्वरूप प्रचंड मौसम की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। हाल ही देश ने चक्रवात और असामयिक बाढ़ को झेला है। इनसे यह स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन एक तात्कालिक चिंता का विषय है। आपदा पर ध्यान दिए बिना तेजी से शहरी विस्तार शहरों को असुरक्षित बना देता है। अनौपचारिक बस्तियां, अपर्याप्त जल निकासी प्रणालियां और हरित स्थानों की कमी इन जोखिमों को बढ़ाती है। इसके अलावा, जैसे-जैसे भारत अपनी तकनीकी वृद्धि जारी रख रहा है, रासायनिक लीक से लेकर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर साइबर हमलों तक मानव निर्मित आपदाओं का खतरा भी बढ़ रहा है।

अब हम यहां से कहां जाएंगे? प्रमुख रणनीतियों में से एक सामुदायिक सहभागिता है। स्थानीय समुदायों को अपने अमूल्य स्वदेशी ज्ञान के साथ, आपदा तैयारियों में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए। वे प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और तत्काल राहत कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वास्तविक समय की निगरानी, पूर्वानुमानित विश्लेषण और संचार के लिए प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने से प्रतिक्रिया समय और संसाधन आवंटन में भारी वृद्धि हो सकती है। इसके साथ ही, आपदा-रोधी बुनियादी ढांचे में निवेश करने की सख्त जरूरत है, चाहे वह भूकंप प्रतिरोधी इमारतें हों या बेहतर जल निकासी व्यवस्था हो। जोखिमों की निरंतर विकसित होती प्रकृति को समायोजित करने के लिए नीति और रूपरेखाओं की समय-समय पर समीक्षा और अद्यतन किया जाना भी आवश्यक है।

अंत में, एनडीआरएफ और अन्य आपदा-शमन संस्थानों ने न केवल भारत, बल्कि विदेशों में भी अपनी व्यावसायिकता से छाप छोड़ी है। उन संगठनों को लगातार मजबूत करने और प्रशिक्षित करने की जरूरत है, ताकि संकट के समय में भारत सहयोग के अपने बड़े हाथों के साथ खड़ा रह सके। हालांकि भारत ने पिछले दशकों में आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन आगे की राह में कई चुनौतियां हैं। तैयारी, अनुकूलनशीलता और सरकारी एजेंसियों, नागरिक समाज और जनता का सामूहिक प्रयास यह तय करेगा कि हम भविष्य की प्रतिकूलताओं का सामना कैसे करेंगे। यदि इस ओर भारत एकाग्रता से काम करें, तो भारत आपदा प्रबंधन में वैश्विक मानक स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। ■

(लेखक पूर्व महानिदेशक, सीआईएसएफ एवं एनडीएमए के दो बार के सदस्य रहे हैं साथ ही सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति हैं)

रामेश्वरम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम पर लिखी पुस्तक का लोकार्पण किया। इस पुस्तक के माध्यम से लेखक स्मृतियों के करीब ले जाते हैं और नई पीढ़ी को नई ऊंचाइयों पर उड़ान भरने के सपनों को सौंपते हैं।

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में विवेकानंद मेमोरियल हाउस का दौरा किया। इस दौरान श्री शाह ने स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए कहा कि आज उस महान संत को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने भारत को एक नए आध्यात्मिक पुनर्जागरण के लिए जागृत किया।

पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉ. खादर वल्ली ने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो मुख्यालय में 'श्री अन्न' पर अखिल भारतीय पुलिस सेमिनार को संबोधित किया। इस अवसर पर पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के महानिदेशक श्री बालाजी श्रीवास्तव ने उनका स्वागत किया। ब्यूरो के अधिकारियों के साथ-साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राज्य पुलिस सहित केंद्र शासित प्रदेश पुलिस के 400 कर्मियों ने हाइब्रिड मोड में सेमिनार में भाग लिया।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के 'पुलिस और सेवा' अभियान के तहत मेघालय को नशा मुक्त बनाने की मुहिम में जुटी। डॉ. एल. आर. बिश्नोई, आईपीएस, डीजीपी, मेघालय ने लोगों से खासतौर से युवाओं और मीडिया से अपील की वे ड्रग के खिलाफ जंग में मेघालय पुलिस की मदद करें। पिछले महीने में 200 से ज्यादा कार्यक्रम स्कूल व कॉलेजों में ड्रग के खिलाफ जागरुकता फैलाने के लिए आयोजित किए जा चुके हैं। उन्होंने जनता से कहा कि ड्रग को 'नो' और 'येस' टू हेल्थी लाइफ कहें।

भारत के वीर

देश के जवानों को श्रद्धांजलि और समर्थन https://bharatkeveer.gov.in

दिशा-निर्देश

- आप सीधे भारत के वीर के खाते में (अधिकतम ₹15 लाख तक) दान कर सकते हैं या भारत के वीर कोष में दान कर सकते हैं।
- अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, प्रति वीर ₹15 लाख की सीमा तय की गई है और यदि राशि ₹15 लाख से अधिक है तो दाता को सतर्क किया जाएगा, ताकि वे या तो अपने योगदान को कम करने या योगदान के हिस्से को किसी अन्य भारत के वीर के खाते में डालने का विकल्प चुन सकें।
- भारत के वीर फंड का प्रबंधन प्रतिष्ठित व्यक्तियों और समान संख्या में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की एक समिति द्वारा किया जाएगा, जो आवश्यकता के आधार पर भारत के वीर परिवार को समान रूप से फंड वितरित करने का निर्णय लेंगे।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) के लिए फार्च्यूना पब्लिक रिलेशंस प्रा. लि. नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित व विबा प्रेस प्रा.लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित

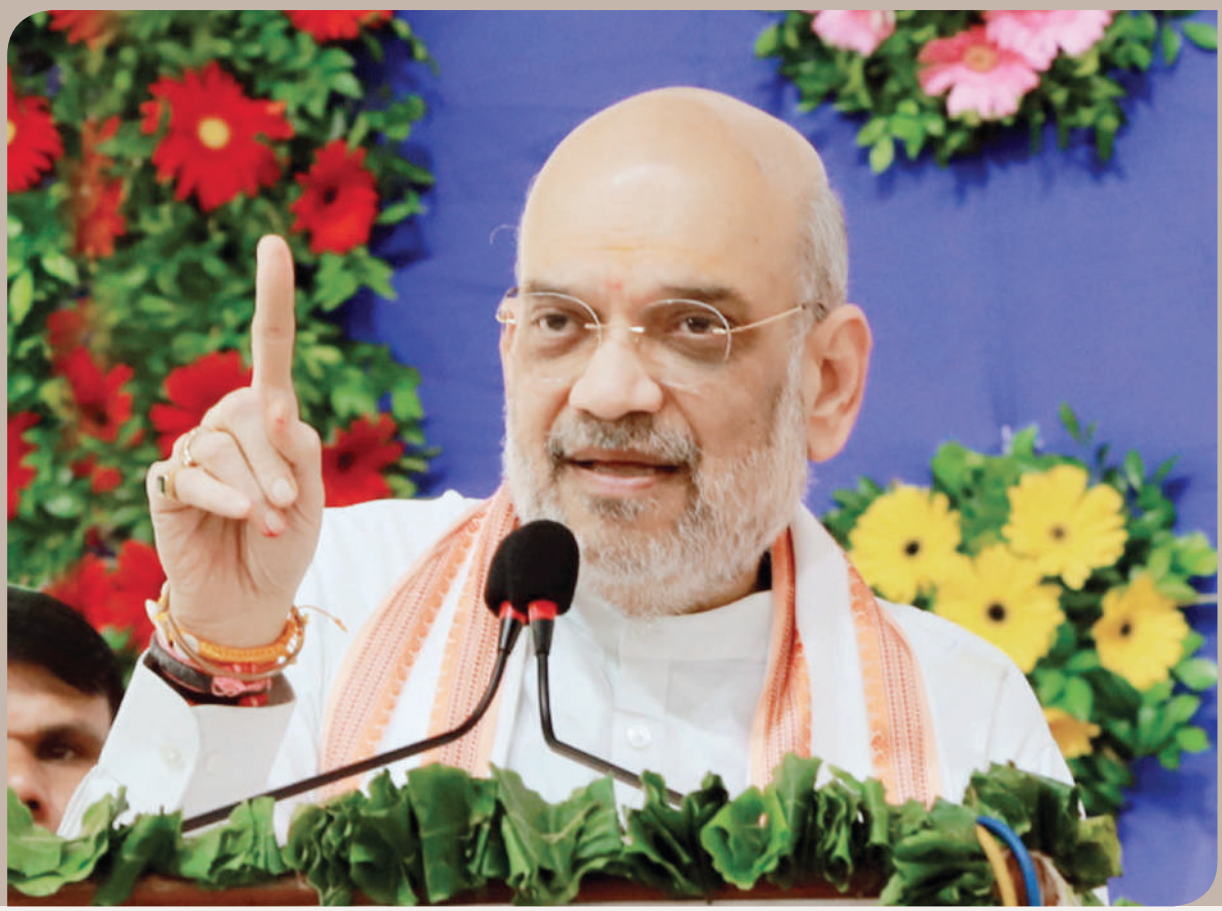

साझा प्रयासों के कारण हमने न सिर्फ आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करने में सफलता हासिल की है बल्कि अच्छी व्यवस्था के साथ पड़ोसियों को मदद करने और पूरे क्षेत्र में अर्ली वॉर्निंग सिस्टम स्थापित करने की दिशा में भी अनुकरणीय काम किया है।

-श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग-48, महिपालपुर,
नई दिल्ली-110037